

वैचारिकी

VAICHARIKI

खण्ड :1 अंक : 2 जुलाई – सितम्बर 2022



DR. R. S. TOLIA UTTARAKHAND ACADEMY OF ADMINISTRATION, NAINITAL – 263001

डॉ० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

कॉपीराईट : डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

2022

खण्ड : 1

अंक : 2

जुलाई –सितम्बर,

संरक्षक : बी0 पी0 पाण्डेय, आई.ए.एस.
महानिदेशक,
डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।

वैचारिकी डॉ0 आ0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है।

वैचारिकी में लेख तथा समीक्षाओं आदि के विषय में पत्र व्यवहार सम्पादक, वैचारिकी, डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल – 263001 से करें।

वार्षिक चन्दा : रू0 1000.00 (संस्थाओं के लिए)

रू0 500.00 (व्यक्तिगत)

आवरण पृष्ठ चित्र : हरीश चन्द्र सिंह पिलखवाल

अस्वीकरण : वैचारिकी में प्रकाशित लेख तथा उसमें प्रस्तुत विचार लेखक के निजी विचार हैं। इससे डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल का कोई संबंध नहीं है।

सम्पादक



सन्देश

डॉ.आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल; उत्तराखण्ड राज्य के शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शोध कार्यों एवं प्रकाशनों के माध्यम से सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु निरन्तर प्रयासरत रही है। इसी क्रम में 'वैचारिकी पत्रिका', जिसका प्रकाशन दो दशकों पश्चात् इस वर्ष पुनः प्रारम्भ किया गया है; का दूसरा अंक पाठकों हेतु प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। इस पत्रिका का उद्देश्य प्रशासकों हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण आयामों यथा शासकीय नियमों प्रशासन के क्षेत्र में नवाचारों, उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी आदि को संकलित कर वृहद उपयोगार्थ प्रस्तुत करना है।

पत्रिका में विभिन्न विषयों से संबंधित आलेख समाहित किये गये हैं जो कि सुशासन हेतु नवीन सन्दर्भ एवं दृष्टि प्रदान करते हैं। साथ ही जनपदों के प्रयास जो कि सफलता की कहानियों में परिणत हुए हैं; हेतु एक नया अध्याय 'प्रयासों की कहानी, जनपदों की जुबानी' जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य परीक्षित एवं सफल (Tested and Successful) प्रयासों को एक मंच प्रदान करना है जिससे कि इनका एक जनपद से दूसरे जनपद में प्रसार हो सके।

इस पत्रिका को प्रशासकों के उपयोगार्थ अधिक प्रभावी बनाने हेतु मांग आधारित बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अतः यदि प्रशासन हेतु आवश्यक किसी विषय विशेष पर आवश्यक जानकारी चाहते हों तो कृपया सम्पादक वैचारिकी के नाम पत्र प्रेषित कर सकते हैं। संबंधित आलेखों को आगामी अंकों में समाहित करने का प्रयास किया जायेगा।

वैचारिकी के आगामी अंक हेतु आपके द्वारा अथवा आपके आस-पास हो रहे अभिनव प्रयासों के आलेख प्रतीक्षित रहेंगे। आशा है यह अंक आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित।

(बी.पी. पाण्डेय)
महानिदेशक

संरक्षक : श्री बी० पी० पाण्डेय, आई.ए.एस.
महानिदेशक,
डॉ० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।

संयोजक : श्री प्रकाश चन्द्र, पी०सी०एस०
संयुक्त निदेशक (प्र०),
डॉ० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

संपादक : डॉ० मंजु ढौंडियाल,
विशेष कार्याधिकारी,
डॉ० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

अतिथि संपादक : श्रीमती रश्मि पाण्डे
विशेष कार्याधिकारी, (से० नि०)
डा० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

सहयोग :

1. सुश्री पूनम पाठक,
उप निदेशक,
डॉ० आर०एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
2. श्री मनोज पाण्डे,
प्रभारी,
शहरी विकास प्रकोष्ठ, सी०जी०जी०,
डॉ० आर०एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
3. श्री आनन्द कुमार,
सह समन्वयक,
प्रशिक्षण एवं समन्वयक इकाई,
डॉ० आर०एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
4. सुश्री रागिनी तिवारी,
कन्सलटेन्ट,
की० रिसोर्स सेन्टर, सी०जी०जी०,
डॉ० आर०एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।

विषय सूची

क्र. सं.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1	A Tribute to the Revolutionaries of Garhwal Against British Rule	Dr. Ajay Singh Rawat, Retd. Professor Department of History, Kumaon University.	
2	National Education Policy-2020: State Initiatives & Challenges	Dr. Kamaksha Mishra, NEP Cell, SCERT Uttarakhand	
3	Ready to Fruit (RTF) Bags- A Novel Concept to Enhance Household Nutrition Through Mushrooms	Dr. Meera Pandey Principal Scientist, Mushroom Research Lab, Indian Institute of Horticultural Research Hessaraghatta, Bangalore	
4	Online Building Permit Approval System (e-Governance Practice) The eASE-App (Electronic Authority Services Enabling Application)	Meenu Pathak Nodal Officer, COMMIT, DRST UAoA	
5	Disasters in Uttarakhand : Himalayan Region	Dr. Om Prakash In-Charge Disaster Management Cell, Dr. R.S.T. Uttarakhand Academy of Administration, Nainital	
6	Skill Development Ecosystem: A Plethora of Initiatives and Opportunities	Ragini Tewari, Consultant Key Resource Centre-WATSAN, Centre for Good Governance, UAoA, Nainital	
7	Faith Healing in Garhwal Region of Uttarakhand	Vikas Singh Public Health Professional	
8	बेरोजगारी एवं पलायन में न्यूनता लाने का एक छोटा सा प्रयास	कैलाश चन्द्र भट्ट सीनियर सलाहकार/टीम लीडर जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, अल्मोड़ा	
9	गढ़वाल उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति के संवाहक लोकगीत	पद्मश्री डॉ. माधुरी बड़थवाल लोक संस्कृति संवाहिका।	
10	किशोर स्वास्थ्य में निवेश क्यों करें ?	Ms. Vimla Makhlova State Project Coordinator State Hub for Empowerment of Women Women Empowerment and Child Development Department Uttarakhand	

11	डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी पुस्तकालय : एक परिचय	आनन्द कुमार पुस्तकालयाध्यक्ष (अ.प्रा.) डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल	
12	उत्तराखण्ड में कृषि, पशुपालन एवं महिलायें	प्रो0 बी0आर0पंत, भूगोल विभाग, एम0 बी0 रा0 स्ना0 महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	
13.	प्रयासों की कहानी जनपदों की जुबानी		
13.1	Installation of Solar Lift Irrigation Scheme, Village Lugar, Block Okhalkanda, District Nainital	Minor Irrigation Division, Nainital	
13.2	मनरेगा तालाब से स्त्रोतों का पुनरुद्धार एवं भूमिगत जल में वृद्धि	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रुद्रप्रयाग के सौजन्य से	
13.3	कीवी के उत्पादन से आय में हुई दोगुनी वृद्धि कीवी उत्पादन कलस्टर ग्राम पंचायत बजीरा	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़ के सौजन्य से	
13.4	जल संरक्षण जीवन संरक्षण नैना झील पुनरुद्धार	मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग के सौजन्य से	
13.5	पशु प्रजनन फार्म नरियालगांव चम्पावत में हाइड्रोपोनिक्स चारा मशीन	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी चम्पावत के सौजन्य से	
13.6	डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, चम्पावत	सहायक निदेशक डेरी विकास एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चम्पावत के सौजन्य से	
13.7	छुरपी को बढ़ावा देना	सहायक निदेशक डेरी विकास एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी चम्पावत के सौजन्य से	
13.8	अल्मोड़ा में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अभिनव प्रयास	मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा के सौजन्य से	
13.9	गोलजू स्वयं सहायता समूह बेरीनाग, पिथौरागढ़ द्वारा कृषि यंत्रीकरण की सफलता गाथा	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़ के सौजन्य से	

A Tribute to the Revolutionaries of Garhwal Against British Rule

Dr. Ajay Singh Rawat,
Retd. Professor
Department of History,
Kumaon University.

Garhwal region is not only famous as Devbhumi but it is also known for its intrepid warriors like Rani Karnavati and Madho Singh Bhandari who challenged the might of the Mughals. The military traditions of Garhwalis are more or less undisputed. Germans called the Garhwalis, “Storm Troops of the Allied Forces.” Out of the five Victoria Crosses (V.C.’s) won in Indian Corps by Indians during the First World War when they were in France, two were won by Garhwalis, Darban Singh and Gavar Singh. Darban Singh was the first Indian to be awarded the Victoria Cross and Gavar Singh was arguably the youngest man in the world whom this honour was conferred upon. Out of the ten Military Crosses (M.C.s) awarded to Indians, four went to Garhwalis, out of the eight recipients of the Order of British India, two were Garhwalis.

The British recognized the military talent of the Garhwalis and carefully cultivated the Royal Garhwal Rifles. Their recruitment in the armed forces added to the mobility of the Garhwalis. Undeniably, the brave soldiers of the Royal Garhwal Rifles performed their duties with loyalty, but gradually they came closer to the realities of life. The exposure of these troops to the outside world and particularly the great sweeps of national movement broadened their horizons. In the initial stages it was a period of reluctance, characterized by the refusal of Chandra Singh Garhwali to fire on the Pathans and disobey British orders. Eventually the natural martial instinct of Garhwali troops found expression in the Second World War, when two battalions of the Garhwalis joined the I.N.A. successfully. It is believed that Nana Sahib one of the protagonists of the uprising of 1857 stayed in anonymity in Uttarkashi and the great revolutionary Ras Behari Bose worked secretly in the Indian Forest Research Institute in Dehradun. Here in Tagore Villa meetings of revolutionaries were organized regularly and brainstorming sessions were held to evolve a militant strategy to liberate Mother India from the shackles of slavery.

During the period 1929 to 1933 when the Revolutionary Movement in India peaked, soldiers from Garhwal came to the forefront to sacrifice their lives for the nation. They were imbued with the spirit of nationalism. Chandra Singh Garhwali was

one of the most intrepid freedom fighters whose name is etched in the annals of history.

Chandra Singh Garhwali

He was a great military revolutionary who was born on the auspicious day of 24th December 1891 in Pauri Garhwal district. His early education was in the village, but his real teacher was the rich experience that he gathered in the British Army and the long term of imprisonment, which he faced with indomitable courage and fortitude for the freedom of the country. Even though he was serving the British Army, he was greatly influenced by the Gandhian philosophy and the soaring spirit of nationalism that had swept the country. He was also an ardent supporter of the Arya Samaj Movement. It is believed that when Chandra Singh Garhwali met Gandhi ji, he asked him why he was donning the alien cap. Garhwali immediately replied that if he desired, he could change the cap. When Gandhi ji presented him a 'Khadi Topi', he pledged from within that one day he would sacrifice his life for the honour of the Gandhian cap. Indeed the opportunity came soon. In 1930 during the Salt Satyagraha Movement, Chandra Singh's battalion (2/18) Royal Garhwal Rifles) was posted in Peshawar. Chandra Singh often slipped out from his unit and went to the bazaar to collect newspapers that were banned in the cantonment area. During night he and his supporters, Harak Singh Dhapola, Narain Sigh Gosain, Keshar Singh Rawat, Mahendra Singh Batela, and Mahendra Singh Negi related the political happenings of the country to his fellow troops and sensitized them for the opportune moment to quit army and join the National Movement on behest of the Congress. The British Commander Martin on the other hand was instigating the Garhwali troops that they might have to shoot the local Muslims to protect the honour of the Hindus. Chandra Singh who wielded tremendous influence in his battalion was addressed as 'Ustad ji' by the Garhwali soldiers. He and his companions foiled the British Commander's attempt to drive a wedge between the Hindus and Muslims.

On 23rd April 1930 Captain Rickett with 72 Garhwali soldiers was deployed to Kissa Khani Bazar of Peshawar. The Garhwali troops entered the gate of the bazar in two files. Down below thousands of unarmed Pathans and a sizeable number of Khan Abdul Gaffar Khan's supporters were picketing shops and dissuading the shopkeepers from selling British goods. Captain Rickett ordered the crowd to vacate the bazaar, but his orders fell on deaf ears. Concomitantly a British platoon fired blank rounds. When the people did not disperse and openly defied the order of the British officer he

ordered the Garhwali soldiers to fire three rounds at them. Chandra Singh Garhwali who was standing on his left hand side intervened and shouted “Garhwalis don’t fire.” The troops obeyed the order of their ‘Ustad ji’ and put their weapons on the ground. It was an act of sheer grit and manifestation of the highest level of intrepidity by Chandra Singh Garhwali and the Garhwali troops. It was the first time in military history of the world when soldiers disobeyed the order of their commander to fire on unarmed people. It was a memorable event in the history of mankind and freedom struggle and the highest order of sacrifice exhibited by the Garhwali troops. They were immediately arrested and at the court martial proceedings the Garhwalis said, “We will not shoot our unarmed brethren.” Frank Moraes, the author of *‘Witness to an Era’*, is of the view that the incident shook the British. It had far reaching effects in Garhwal also. The incident occurred on 23rd April 1930, and thereafter efforts were made to join hands with Garhwali troops at Lansdowne by the Congressmen. In a letter, dated 14th June 1930, General J.S.M. Shea, General Officer Commanding in Chief, Eastern Command had tendered information to the Chief of the General Staff, Army Headquarters, Simla, in this connection. He wrote, “Efforts are being made to tamper with the Garhwali troops at Lansdowne and Congressmen are now in Lansdowne with that object.”

According to Chandra Singh Garhwali “For this act of disobedience, the troops of the 2/18 Royal Garhwal Rifles were given five years of departmental punishment. Sixty seven soldiers were dismissed and sixteen rank holders were given three to twenty years of rigorous imprisonment.” Chandra Singh Garhwali was awarded death sentence, which was later reduced to life imprisonment against his wish. He stated when I met him ten days before his demise that he did not wish, “The Congress should beg for my life, when I took this drastic step I knew that I shall go to the gallows. My desire was to die for my country as a martyr.”

General Mohan Singh of the Indian National Army (INA) fame remarked that “The two battalions of the Garhwal Rifles, which joined the INA were inspired by Chandra Singh Garhwali’s example.” A letter dated 14th June 1930, from the GOC Eastern Command to Army Headquarters stated “After this incident attempts are being made to undermine the loyalty of the Garhwalis at Lansdowne and of the Kumaonis at Almora by the Congressmen.”

Revolutionaries from Garhwal.

Chandra Singh Garhwali is the best example of a militant challenge, which inspired revolutionary upsurges against the alien regime. The intrepidity of Chandra Singh Garhwali and the Revolutionary Movement in India, which peaked during 1929 to 1933 inspired the youths of Garhwal and three young revolutionaries from Garhwal, Bhawani Singh, Indra Singh and Bachhu Lal. They associated themselves with the mainstream of Indian consciousness and joined hands with the great revolutionaries, Chandra Shekhar Azad, Shambhu Nath Azad, Roshan Lal and others. Their main objective was to organize armed revolution to end the colonial rule and establish a Federal Republic. Bacchu Lal took active part in the Ooty Bank Dacoity and Bhawani Singh was directly involved in the Gadodia Store Robbery in Delhi, which was accomplished very successfully. The revolutionaries were in acute need of funds and in July 1930 Chandra Shekhar Azad co-opted Kashi Ram, Bhawani Singh and others for this robbery. The revolutionaries looted the store and carried away Rs. fourteen thousand. The amount was later used to fund a bomb factory. Indra Singh was an active member of the Madras Bomb Case and was awarded 20 years life imprisonment in Andamans.

Role of Garhwalis in the Indian National Army

Neta ji Subhash Chandra Bose was one of the most prominent leaders of the Indian Freedom Struggle and his name has become synonym with the Indian National Army. He was born on 23rd January 1897 in Cuttack in Orissa. His father Jankai Nath Bose was a famous lawyer and his mother Prabhawati Devi, a pious and religious lady. Subhash Chandra Bose was an exceptionally brilliant student and was strongly influenced by Swami Vivekananda's teachings. To fulfill his parent's desire Subhash Bose went to England in 1919 to compete for the Indian Civil Services (ICS) Examination. In 1920 he appeared for the ICS and stood fourth in the order of merit. It was the elite higher civil service of the British Empire in South Asia. The ICS officers were very powerful; they held all the key positions and were ultimately responsible for overseeing every government activity in British India.

Imbued with a spirit of nationalism, Subhash Bose was deeply disturbed by the Jallianwala Bagh Massacre and left the ICS training midway. He returned to India in 1921 and joined the Indian National Congress. Under Gandhi ji's instruction he started working with Deshbandhu Chitranjan Das whom he later acknowledged as his mentor. Bose became very popular in the Congress and was elected as its president in

1938. 1939 under his leadership in the Congress, he formed the Forward Bloc as a left wing party within the Congress. In August the same year he started the publication of the newspaper titled "Forward Bloc." But his greatest contribution was of carrying the legacy of Ras Behari Bose, the founding father of the Indian National Army (INA) in 1942. He was a great revolutionary leader who played a crucial role in the Ghadar Revolution, a plan to attack the British Army from within. Subhash Bose was invited to take over charge as Supreme Commander of the INA in Singapore on 25th August 1943.

Veer Kesari Chand

In Uttarakhand there was a mass following of Subhash Bose and several soldiers from the hills joined the INA. Veer Kesari Chand from Jaunsar Babar was one of the youngest Indian who sacrificed his life for the country." He was arrested by the British troops for blowing a bridge in the Imphal front and was hanged in Delhi jail on 3rd May 1945 when he was only 24 years and six months. Even today an annual fair is held in April in Ram Tal Tahsil of Chakrata to commemorate his highest sacrifice for the country. Other brave warriors from Kumaon about whom there is information are, Dhanpat Singh Bisht, Kalu Singh (Kalyan Singh) Gopal Singh, Chandra Shekhar Khulbe, Captain Ram Dutt Pant, Major Keshav Dutt Pande, Shiv Singh Thapa, Captain Ram Singh,, J. S. Pande, Umed Singh Sugra, Fateh Jung Bahadur Rana, Amreek Singh Puniya, Doongar Singh and others

Shiv Singh Thapa from the INA stated that "Two battalions 2/18 and 5/18 of Royal Garhwal Rifles joined the INA. There were 2500 Garhwalis in these two battalions out of which 600 were killed in action." Subhash Bose reposed tremendous faith on the hill troops and was aware of their martial qualities, integrity and loyalty. He was so impressed with their indomitable courage and integrity that they were assigned very important positions in the INA. Lt. Colonel Chandra Singh Negi was appointed Commander of the Officers Training School in Singapore. Major Deb Singh Danu was deployed as Commander of the personal guard's battalion of Subhash Bose. Lt. Colonel Buddhi Singh Rawat held the esteemed position as personal adjutant of Subhash Bose. Lt. Colonel P.S.Raturi was commanding the first battalion and Major Padam Singh Gosain the third battalion of Subhash Regiment. For his gallantry and outstanding qualities of leadership, Raturi was decorated with the gallantry award Sardar-e-Jung by Neta ji himself.

During the Burma Campaign in 1944, Raturi's battalion saw action in the Arakan front. The troops under his command occupied Mowdok and the various posts around it. Shah Nawaz Khan in his memoirs 'My Memories of INA and its Neta ji' has written that the attack on Mowdok was launched at night with a lightning speed. It came as a complete surprise to the well-equipped British troops who fled leaving behind large quantities of ration and ammunition. Philip Mason, the then Joint Secretary of the War Department in India has extolled the intrepidity of the Garhwali troops and their love for the motherland. He said "The behavior of these battalions and their troops was I believe typical of many. They were imbued with an element of nationalism."

National Education Policy-2020: State Initiatives & Challenges

Dr.Kamaksha Mishra,

NEP Cell, SCERT Uttarakhand

The National Education Policy-2020 has come into existence 34 years after the National Education Policy of 1986. It is seen as a paradigm shift in the pre-existing education system of the country.

It is heartening to know that the policy has just celebrated its second anniversary on July 29th, 2022. At the same time, this should also be taken into consideration that strong strategies are to be formulated for its effective implementation in the states so that it could be incarnated in its true essence. To quote, “The purpose of the education system is to develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination, with sound ethical moorings and values. It aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our Constitution.”

With this purpose in mind, the Government of India has planned to implement the policy within the scheduled time span of ten years i.e. till the year 2030, making the State Councils of Educational Research & Training as nodal agencies for each state.

Some Salient Features of NEP-2020

- This policy envisages that the existing 10+2 structure in school education will be modified with a new pedagogical and curricular restructuring of 5+3+3+4 covering ages 3-18 years.

Currently, children in the age group of 3-6 are not covered in the 10+2 structure as Class 1 begins at age 6. In the new **5+3+3+4 structure**, a strong base of Early Childhood Care and Education (ECCE) from age 3 is also included, which is aimed at promoting better overall learning, development, and well-being.

- It is envisaged that prior to the age of 5 every child will move to a 'Preparatory Class' or '**Balvatika**' (that is, before Class 1), which has an ECCE-qualified teacher. The learning in the Preparatory Class shall be based primarily on play-based learning with a focus on developing cognitive, affective and psychomotor abilities and early literacy and numeracy.

- The highest priority of the education system will be to achieve **universal foundational literacy and numeracy** in primary school by 2025.
- As per the 75th round household survey by NSSO in 2017-18, the number of out of school children in the age group of 6 to 17 years is 3.22 crores. It will be a top priority to bring these children back into the educational fold as early as possible, and to prevent further students from dropping out, with a goal to achieve **100% Gross Enrolment Ratio** in preschool to secondary level by 2030.
- Students will be given **increased flexibility and choice of subjects** to study, particularly in secondary school - including subjects in physical education, the arts and crafts, and vocational skills – so that they can design their own paths of study and life plans. Holistic development and a wide choice of subjects and courses year to year will be the new distinguishing feature of secondary school education. There will be no hard separation among ‘curricular’, ‘extracurricular’, or ‘co-curricular’, among ‘arts’, ‘humanities’, and ‘sciences’, or between ‘vocational’ or ‘academic’ streams.
- It is proposed to set up a **National Assessment Centre**, PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development), as a standard-setting body under MHRD that fulfills the basic objectives of setting norms, standards, and guidelines for student assessment and evaluation for all recognized school boards of India, guiding the State Achievement Survey (SAS) and undertaking the National Achievement Survey (NAS), monitoring achievement of learning outcomes in the country.
- By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a **4-year integrated B.Ed.** degree that teaches a range of knowledge content and pedagogy and includes strong practicum training in the form of student-teaching at local schools.

State Initiatives regarding NEP-2020

SCERT Uttarakhand is the nodal agency for effective implementation of the policy in the state within due time making convergence with the concerned bodies/departments. Some important initiatives taken by the state are mentioned as under:

- 1. Balvatika Preparatory Class-** As recommended in the policy, Uttarakhand has become the first state to have successfully launched the ‘Balvatika’ preparatory

class in the month of July this year for children of five to six years, i.e. before class I. In the first phase, only the Anganwadi Centers have been taken into consideration. Other centers are also to be covered in the next phase till 2026.

- 2. NIPUN Bharat Mission-** The National Mission on Foundational Literacy and Numeracy is set up by the Ministry of Human Resource Development. Under this, stage-wise targets and goals to be achieved by 2025 have been identified. A Programme & Monitoring Unit (PMU) has been set up at state level to closely track and monitor the progress of the programme. ‘Pragati’ app has also been developed for the online assessment of the programme.
- 3. Grouping of Schools as School Complexes-** The theme behind establishing school complexes is sharing of resources, both physical and human, to energize and empower the schooling system in a resource-efficient manner. A school complex will have one secondary school together with all other schools offering lower grades in its neighborhood including Anganwadis, in a radius of five to ten kilometers. The School Education department of the state has identified 192 school complexes in the first stage covering rest of the schools in the coming future.
- 4. Kaushalam: A step towards Vocational Education-** It is an endeavour to incorporate vocational education with mainstream education as per NEP-2020 recommendations. The Kaushalam curriculum has been started for students of class-IX with a vision to introduce the concept of entrepreneurship in young minds so that they’ll be able to identify and explore the locally available opportunities in the environment. Secondary section upto class-XII will also be covered in the coming years.
- 5. Change in Teacher Training pattern-** The NEP-2020 talks of four years integrated teachers’ training package which will include pre-primary to secondary teaching. Besides, it also recommends a two years B.Ed programme for graduates which have been started in the state.
- 6. Mother Tongue as a Medium of Instruction in Elementary Classes-** The policy staunchly recommends the use of mother tongue in primary classes till elementary level to make the learning environment amicable for the child so that he may grab maximum learning opportunities in his initial years. For this, supplementary reading material called BARKHA Series developed by NCERT has been translated into Kumauni, Garhwali, Jaunsari and Gurumukhi. To add colours to this, the state is about to celebrate ‘Matribhasha Utsav’ on the 2nd & 3rd of November this year. The

purpose of the programme is to promote regional languages and make children proud of their mother tongue.

7. State School Standards Authority- At present, all main functions of governance and regulation of the school education system are handled by a single body, i.e., the Department of School Education or its arms. This leads to conflict of interests and excessive centralized concentration of power. It also leads to ineffective management of the school system, as efforts towards quality educational provision are often diluted by the focus on the other roles, particularly regulation, which the Departments of School Education also perform.

To avoid all this, NEP-2020 recommends an effective quality self-regulation or accreditation system for all stages of education including pre-school education - private, public, and philanthropic - to ensure compliance with essential quality standards. In this regard, the state of Uttarakhand has issued a government order to set up an independent, State-wide, body called the State School Standards Authority (SSSA). This authority will establish a minimal set of standards based on basic parameters (namely, safety, security, basic infrastructure, number of teachers across subjects and grades, financial probity, and sound processes of governance), which shall be followed by all schools. Presently, SCERT is working on the framework for these parameters.

To conclude, NEP-2020 has great potential to improve the current education system but it is also difficult to visualize how things would be implemented on ground. For instance, the policy talks of the 5+3+3+4 formula in place of the old 10+2 formula. The first five years or foundational years include the three years of early childhood care and education which is a part and parcel of Women Empowerment and Child Development Department. So a strong convergence between the two departments is the need of the hour for improving the quality of school education. Similarly, the multidisciplinary approach or the wide subject choice for students would be a revolutionary step but how will it contribute to the future career options where subject specialization is required, is a mystery. If we talk of SSSA, bringing public and private sector schools of different boards on the same platform would be a challenge. But as we, the State of Uttarakhand, have already embraced and adopted the policy, we are determined to come off with flying colours and avail the best out of it.

Ready to Fruit (RTF) Bags- A Novel Concept to Enhance Household Nutrition Through Mushrooms

Dr. Meera Pandey

Principal Scientist,

Mushroom Research Lab,

Indian Institute of Horticultural Research Hesaraghatta,

Bangalore

There are about 1500 varieties of mushrooms which are edible of which about 600 varieties are of exclusive medicinal valued. Among the culinary medicinal mushrooms, Oyster mushrooms is the easiest to grow and highly suitable for Indian climate. Mushroom Research Lab at IIHR has initiated the concept of RTF bags for oyster mushrooms which ensures that oyster mushroom can be easily grown at home.

Introduction

Mushrooms are storehouse of excellent nutritional and medicinal components to enhance nutrition and health. Daily intake of mushrooms is a very common thing in south East Asia. However, it has yet to find place in the culinary menu of Indian families. Among the many reasons, the lack of awareness, non-availability in common stores and high cost are prominent reasons for non-adoption as daily intake. There are about 1500 varieties of mushrooms which are edible of which about 600 varieties are exclusive medicinal valued. Among the culinary medicinal mushrooms, Oyster mushrooms is the easiest to grow and highly suitable for Indian climate.

Nutritional and Medicinal Potential of Oyster Mushroom

Nutritional potential:

Oyster mushrooms are one of the most hygienic and chemical free vegetables that are full of nutrients and therefore can make a very valuable contribution to human nutrition especially in a country like India where the predominantly vegetarian population suffers from acute malnutrition. They are hygienic because the paddy straw or any other agricultural waste which is used to grow them is steam sterilized at 121°C for 15-30 minutes. No chemical is used at all during their growth phases; hence, they are totally chemical free. Oyster mushrooms are a rich source of proteins (3-4% on fresh weight basis and 25-35% on dry weight basis). It can therefore, be an important protein source among the vegetarians. As a dietary source of proteins, mushrooms are superior to most common fruits and vegetables with the exception of beans and peas.

Mushrooms can be eaten fresh in salads or cooked unlike soya or yeast which has to be processed before they are acceptable on the table. Mushrooms contain all the essential amino acids. Lysine is the most important amino acid in mushrooms which is low in cereals. Mushrooms rank very high in vitamin content especially B vitamins as compared to most of the common vegetables eaten in the Indian diet. The riboflavin, thiamin, Vit. B12, and niacin content of mushrooms is very high. Mushrooms are the only vegetarian source of vitamin D, which is deficient in majority of the Indian population. Sun dried oyster mushrooms become a very good source of vitamin D and can take care of the most of the daily requirement of Vitamin D in humans. Oyster mushrooms are a very good source of minerals like iron, Zinc, potassium, phosphorus and folic acid. Mushrooms contain high amounts of antioxidants like ergothioneine.

Medicinal potential:

Mushrooms have been valued by the millennia for their medicinal properties. Historically hot water soluble fractions (decoctions and essences) from medicinal mushrooms i.e. mostly polysaccharides were used as medicine in the Far East, where knowledge and practice of mushroom use primarily originated. Oyster mushrooms are low fat, zero cholesterol, high fiber and low energy food hence, excellent for diabetics. Oyster mushrooms are also known to reduce blood lipid levels. Due to very low sodium, they are also regarded as excellent diet for reducing blood pressure. Due to their high iron and folate content, oyster mushrooms are often called as blood builders. The mushroom if consumed in dry powder form can largely mitigate iron malnutrition. The zinc content too is high which can manage the zinc deficiency of the Indian population. Oyster mushrooms are also known to possess anti-tumor and immunomodulating properties.

Method: From Bag to Table in 5 Days

Mushroom Research lab at IIHR has initiated the concept of Ready to Fruit (RTF) bags for oyster mushrooms. This ensures that oyster mushroom can be easily grown at home in some humid corner of the backyard. The concept involves providing the seeded and developed (grown) straw bags to the consumer. A slit or hole is to be made by the consumer, light spray of watering to be done and the mushrooms sprout within 5-7 days. A maximum of 10 bags are given to each housewife on prior order basis (25 days advance order). The bags have to be collected from IIHR on any working day on cash payment basis. At present, Elm oyster mushroom and pink oyster mushrooms are being made available. These bags are to be purchased to harvest

excellent healthy mushrooms at home. The harvested mushrooms can be used fresh or sun dried which makes them enriched with vitamin D. The dried mushrooms can be used as such by presoaking in warm water for 15-20 minutes or can be easily powdered in house blender (mixie) at home. The powder and the dry mushrooms can be stored even upto one year (refrigerator) in air tight containers. The powder can be used to enhance the nutrition and flavor of any everyday meal like rasam, chutney poodi, plain rice etc. Thus, an excellent hygienic, chemical free and culinary medicinal mushroom can be a part of your kitchen or terrace garden. All you require is a bottle sprayer and a few minutes for spraying water. IIHR can also help in establishing production units of RTF bag by the Govt. or private agencies so as to make oyster mushrooms a part of our daily menu. One can also generate income by sale of RTF bags through retail stores, vegetable shops, nurseries, etc.



Women carrying RTF bags	Growing mushroom at home	Sun drying mushrooms for long term storage
-------------------------	--------------------------	--

Mushrooms are plants without chlorophyll. They are vegetables which are powerhouse of nutrients. Mushrooms are highly nutritious in terms of proteins, B vitamins, and the lone and excellent source of vegetarian vitamin D, minerals like iron with high bioavailability, potassium and phosphorus. They are recommended food for type 2 diabetic patients due to very low glycemic index and high fiber. They are excellent foods for cardiac health due to very low sodium, high potassium and zero cholesterol. Mushrooms are also immune boosters. Although mushrooms are excellent nutrition source for vegetarians and a very delicious way to reduce the intake of non-vegetarian food they have yet not become a part of daily Indian diet.

Mushrooms often have been projected as food for God and for the Elite. They have been sold at prices beyond the buying capacity of an average Indian family. ICAR-Indian Institute of Horticultural Research,



Hesaraghatta, Bengaluru is the pioneer institute on Mushroom Research in India

which has been consistently working towards making mushrooms as a part of daily Indian diet of every home so that mushrooms in their own humble way may contribute towards country's nutrition security and mitigation of malnutrition.

RTF Technology-

The 'Ready to Fruit' (RTF) Bag technology was developed at ICAR-IIHR in 2013 to bring mushrooms to rural homes in the villages where there is space, skill and resource constraints. The rural women were trained and made aware about the nutritive and health aspects of mushrooms and the ways in which mushrooms could be incorporated to suite their daily diet e.g. Arka Mushroom rasam powder, Arka Mushroom chutney powders, Mushroom Pulyogare powder etc. Women were provided with pre-seeded and fully grown RTF bags which they could hang in their homes and harvest mushrooms in 5-6 days. 250-300g of mushroom can be harvested from each 1 kg RTF bag. If bag opening is done in a planned and staggered way; this technology can make available mushrooms to every home on a daily basis. The RTF bags have not only become popular in resource crunched rural households but also in the urban homes with space constraints. As the household mushroom consumption increases so will the demand for RTF bags. Hence ICAR-IIHR has modeled this technology into an entrepreneurial activity which can be taken up by individuals or on community basis through SHGs or NGOs by investing in establishing RTF bag production unit.

The RTF bag production unit comprises of a straw storage, straw cutting, straw soaking, mixing and bag filling shed, sterilization chamber, inoculation chamber and incubation or growth chamber. Machinery required will be motorized chaff cutter to cut straw, ICAR-IIHR designed multifuel boiler with chamber for sterilization. Efforts can be made to create a rural urban network through RTF bag production so that the rural areas with ample raw material and labor can become the RTF bag production hub which can be marketed in the urban areas. ICAR-IIHR has collaborated with many public, private and Non-Government organizations to establish RTF bag production units. The vision of ICAR-IIHR is to make the RTF technology so popular that anyone can walk up the nearest grocery store and pick up a few RTF bags to grow mushrooms in their kitchen garden.

Online Building Permit Approval System

(e-Governance Practice)

The eASE-App (Electronic Authority Services Enabling Application)

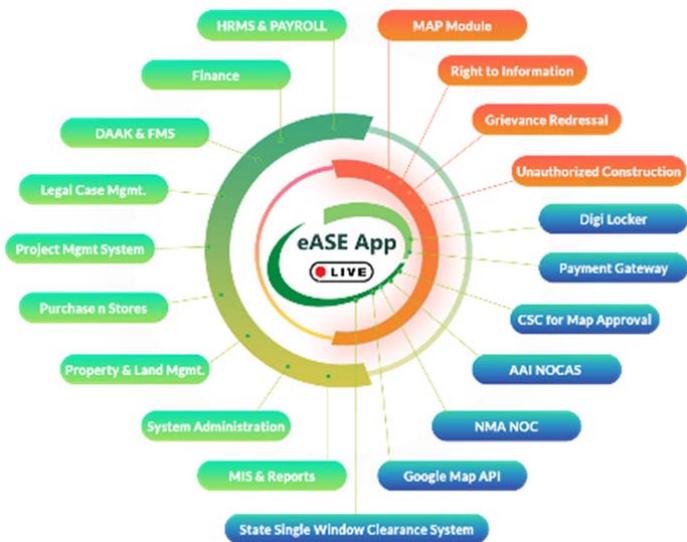
Meenu Pathak

Nodal Officer, COMMIT,

Dr. R.S.T. Uttarakhand Academy of Administration,

Nainital

The current presence and usage of information technology in every aspect of human lives has prominently impacted on the services availed by citizens from government. In the past most of the citizens have faced challenges to avail any type of services related to government. The Department of Housing, Government of Uttarakhand took an initiative in line with the implementation of E-Governance and adaption of digital transformation to automate all its **G2C, G2B & G2G** services rendered through its development authorities across the state of Uttarakhand under its nodal office Uttarakhand Housing & Urban Development Authority (UHUDA). Under the implementation guidelines of Ease of Doing Business (**EoDB**) of Government of India and Digital India (DI) program envisioned for rendering government services and internal processing digitally, the project was initiated as General Services Management Software aka; **eASE-APP (Electronic Authority Services Enabling Application)**.



The project was designed and envisioned to bring a complete paperless **G-G, G-B and G-C** system for the development authorities under UHUDA. This enables the Authority to provide its core services to the public on an **easy-to-use platform**, deliver services with **quick turn-around time** and with **transparency**. The project is developed with the Objectives as:

1. Enable services on a single platform in congruence with the Ease of Doing Business Guidelines to reduce TAT (Turn Around Time) for services.
2. Inclusive Approach to deliver services to the stakeholders to improve citizen centricity.
3. Provide unparalleled transparency and near-zero physical contact points between the stakeholders to promote Good Governance.
4. Dynamic System capable of adapting changes in organisational business process and user level changes as well as enable policy to reflect on application with the shortest of turn-around time.
5. A Seamlessly integrative system to provide access to services of other departments external to the authority at National as well as State/District level.
6. Data Integrity: Bring in data from multiple departments and provide a mechanism to ensure information sharing and interoperability within multiple departments of the authority and sync all information in an easy to access and referenceable form to all users.

To achieve the objective, some of the core features it delivers are:

1. Issue Building Permits for infrastructure constructions.
2. Manage and approve Permits as per the state guidelines and by-laws.
3. Enforcement of Building By-laws on ground.
4. Provide grievances & redressal system to the public for effective and timely resolution.
5. To provide a transparent & non-repudiation system for services to stakeholders.
6. To provides e-Gov solution for Monitoring and Evaluation of infrastructure projects and schemes.
7. The eASE App provides the following services to stakeholders:
 1. Online Building Permit System: This allows users to apply for / pay for / check status for any and all kinds of permits they may require for construction from their homes with zero human touch points, as stated in EODB guidelines.

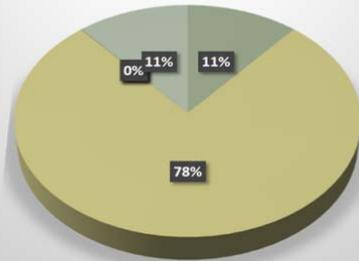
2. Construction By-Laws Verifier System: This allows the users to check and verify their construction drawings with respect to the latest by-laws using the application with no required interfacing with any authorized personnel and rectify the drawing before submission to greatly save on time and money.
3. Public Grievance Redressal System: This allows any user to register their complaints related to permits, illegal constructions, authority users, pending invoices, delayed services etc. It also enables the stakeholders to track the progress on the resolution of the complaint.
4. Unauthorized Construction Management Systems: This enables authorized authority to:
 - (i) Register any illegal constructions within the jurisdiction of development authority.
 - (ii) Issue notices under relevant sections of the prevailing development Act
 - (iii) Track and enable case related hearings with transparency and accountability for complainants and defendant.

Data Representation

**Comprehensive Comparative Analysis (Before and After Initiative) – Data:
Nov, 2017 ~ Dec, 2018 *Offline* and Apr, 2019 ~ Mar, 2022 *Online***

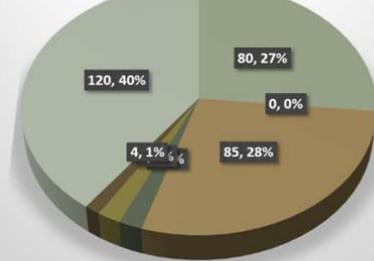
S.N.	Particular	Before Initiative	After Initiative	% increase or decrease (if applicable)
1	Average time for making a complete transaction (Service wise) (in Hours)	720	80	-88.89
2	Average cost for making a complete transaction (Service wise) (in Indian Rupee)	5000	0.5	-99.99
3	% positive feedback out of total feedback received	1	85	8400.00
4	Name and No. of Channels for Service Accessibility (Mobile, Kiosk, website, Govt. office, CSC etc)	1	6	500.00
5	Service Assessment Facility	1	6	500.00
6	Availability of on-call support having ticket number	1	4	300.00
7	Average time to close issues reported through online or offline means (Service-wise) (in Hours)	720	120	-83.33

Citizen Experience Before Initiative



- Average Time for making a complete transaction (in Hours)
- Average cost for making a complete transaction
- Positive feedback
- No. of channels for Service Accessibility
- Service Assessment Facility
- Availability of on-call support having ticket no.
- Average time to close issues reported through online or Offline means

Citizen Experience After Initiative



- Average Time for making a complete transaction (in Hours)
- Average cost for making a complete transaction
- Positive feedback
- No. of channels for Service Accessibility
- Service Assessment Facility
- Availability of on-call support having ticket no.
- Average time to close issues reported through online or Offline means

Disasters in Uttarakhand : Himalayan Region

Dr. Om Prakash

In-Charge Disaster Management Cell,

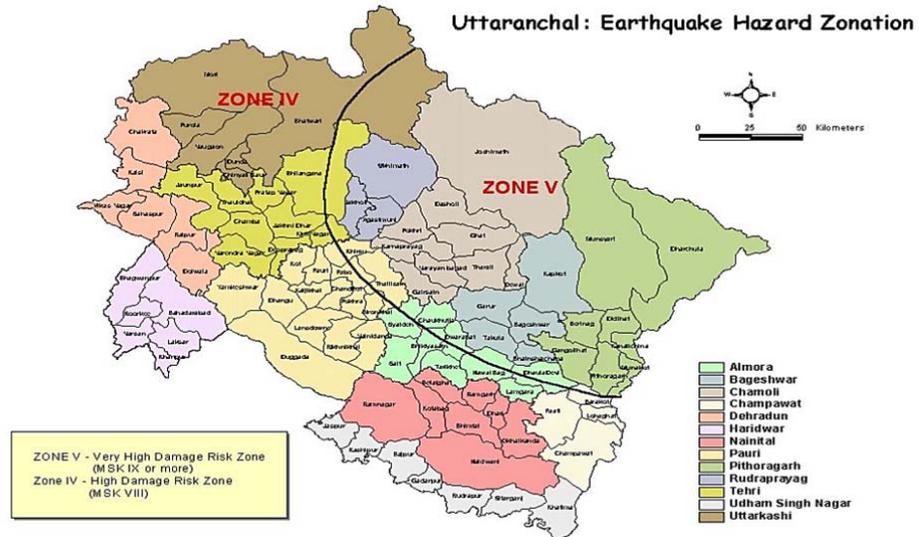
Dr. R.S.T. Uttarakhand Academy of Administration,
Nainital

As per earthquake zonation map of India, the entire region of the state can be covered into two zones, Zone IV and Zone V. The region experienced many earthquakes of small and large scale with their epicenters located within the Himalayan region. The state has witnessed two major earthquakes in the recent past, the Uttarkashi earthquake in 1991 and the Chamoli earthquake in 1999. Nearly 767 people died in Uttarkashi and 106 died in the Chamoli earthquake. The district Bageshwar, Chamoli, Pithoragarh, Rudraprayag and Uttarkashi, which were severely affected in the 2013 flash floods falls within the seismic Zone V.

As shown in the map (fig. 1) four of the thirteen districts of the state (Pithoragarh, Chamoli, Bageshwar and Rudraprayag) entirely fall in Zone V, whereas other five districts (Uttarkashi, Tehri Garhwal, Pauri, Almora and Champawat) fall partially in Zone IV and partially in Zone V and the rest (Dehradun, Haridwar, Nainital and Udham Singh Nagar) fall in the Zone IV of earthquake risk levels.

The state has taken many administrative and operational initiatives under the Disaster Management Act. Broadly speaking, disaster management is divided into prevention, preparedness & rescue-relief strategies. The state government has adopted a multidimensional and multisectoral approach to the challenge of disaster management. Under a pre- disaster management strategy, risk reduction through awareness has become an important element.

Fig. 1



Himalayas & Disasters :

Himalayas, as a region, have always been susceptible to disaster, due to the neo-tectonic mountain-building processes, like earthquakes, landslides, floods, etc. The spread of reckless developmental activities has transformed many natural disasters into man-made events. Such calamities have a negative impact upon the development scenario and exerts additional pressure on an already strained national economy.

Earthquake :

It is important to discuss the origin of the Himalayan Mountains for understanding the natural seismicity in the Himalayas. Around 45 million years (during the Eocene period on Geological Time Scale), India collided with Eurasia. This was due to the continued northward migration of India. Since then, India has penetrated some 2000 km into Asia leading to the creation of Himalayan Mountain Range and this process is still in continuation. In this process, the Himalayan plate is undergoing beneath the Eurasian plate.

Thus, the Himalayan Mountains are the only 'living' mountains in the world as the plate tectonic activities churning within the Himalayas are leading to increase in its height. This internal turbulence within the Himalayas is solely responsible for their active seismic nature as corroborated by a large number of earthquakes traversing the entire belt from time to time, taking a heavy toll of life and property. Overall, more than ninety percent of the earthquakes occurring in India fall within the Himalayan mountain zone and its foothills. Scientifically, it has been experimentally shown that the seismicity creeps in an area through pre-existing zones of weakness and the neo-tectonic activities of Himalayas make it a zone of weakness. In last ten years, two major earthquakes have occurred in Uttaranchal namely the Uttarkashi earthquake (1991) and the Chamoli earthquake (1999).

It should be noted that the damages in the event of an earthquake primarily result from the unplanned developmental activities in seismicity-prone areas, which increase the casualties of life and loss of property manifold. Therefore special attention should be paid in undertaking major developmental activities like human settlements, urbanization, road building, laying of railway tracks etc. Japan, seismically one of the most vulnerable countries, has successfully shown that the damages accruing from an earthquake, even with a higher magnitude of 7 on Richter Scale, can be minimized by adopting an integrated approach of generating awareness, building earthquake resistant structures, always keeping the level of preparedness at a

higher level, and preparing and regular updating of elaborate disaster management plan in case of an eventuality.

Major Earthquakes of Uttarakhand :

S. No.	Date of Occurrence	Magnitude	Affected Area
1.	1 September, 1803	9.0	Badrinath
2.	26 May, 1816	7.0	Gangotri
3.	25 July, 1869	6.0	Nainital
4.	28 October, 1916	7.5	Dharchula
5.	28 October, 1937	8.0	Dehradun
6.	27 July, 1966	6.3	Kapkot, Dharchula
7.	28 August, 1968	7.0	Dharchula
8.	29 July, 1980	6.5	Dharchula
9.	20 October, 1991	6.6	Uttarkashi
10.	29 March, 1999	6.8	Chamoli
11.	01 February, 2006	5.2	Indo-China Boarder
12.	14 March, 2006	5.0	Indo-China Boarder
13.	31 March, 2006	3.1	Chamoli
14.	05 August, 2006	5.0	Indo-Nepal Boarder
15.	27 October, 2006	3.8	Bageshwar
16.	05 February, 2007	3.5	Indo-Nepal Boarder
17.	27 March, 2007	3.2	Uttarkashi
18.	22 July, 2007	5.0	Uttarkashi
19.	07 August, 2007	3.5	Uttarkashi
20.	03 November, 2007	2.7	Uttarkashi
21.	25 January, 2008	3.5	Rudraprayag
22.	13 August, 2008	3.6	Bageshwar
23.	04 September, 2008	5.1	Indo-Tibet Boarder
24.	18 March, 2009	3.3	Uttarkashi
25.	15 May, 2009	4.5	Chamoli
26.	27 August, 2009	3.9	Uttarakhand
27.	21 September, 2009	4.7	Uttarkashi

28.	11 January, 2010	3.9	Pithoragarh
29.	22 February, 2010	4.7	Bageshwar
30.	03 May, 2010	3.5	Uttarakhand
31.	22 June, 2010	4.7	Pithoragarh
32.	24 June, 2011	3.2	Indo-Nepal Boarder
33.	04 July, 2011	3.4	Chamoli, Almora
34.	21 September, 2011	3.1	Uttarkashi
35.	20 November, 2011	3.2	Uttarkashi
36.	09 February, 2012	5.0	Uttarkashi
37.	10 May, 2012	3.9	Chamoli
38.	01 June, 2012	3.7	Chamoli
39.	26 October, 2012	3.5	Chamoli
40.	15 November, 2012	3.2	Pithoragarh, Bageshwar
41.	30 January, 2013	2.6	Bageshwar
42.	11 February, 2013	4.3	Uttarkashi
43.	17 February, 2013	3.2	Uttarkashi
44.	25 February, 2013	3.1	Uttarkashi
45.	06 March, 2013	3.2	Indo-Nepal Boarder
46.	24 March, 2013	2.9	Indo-Nepal Boarder
47.	06 April, 2013	4.3	Rudraprayag
48.	05 September, 2013	3.5	Uttarkashi
49.	07 February, 2017	5.8	Rudraprayag

Fig. 2

Landslides :

Landslides are defined as the mass movement of rocks, debris or earth down a slope dislodging earthen material on its way. Often they are associated with other calamities like earthquakes, floods or volcanoes, involving movement of earth. Prolonged rainfall also causes heavy landslides, especially in mountain areas devoid of vegetation cover, blocking the flow of river. These river blocks, if and when they burst, can cause havoc to the settlements downstream. Landslides are common occurrence in the hilly states of India. For example, 218 people were killed when massive landslides washed away the whole village Malpa, Uttaranchal in 1998. In

year (2003) a number of landslides occurred during the monsoon season triggered by the heavy rains. This led to the blockade of roads in most parts of the state like Shimla-Kalka Road (Himachal-Haryana link Road), the Hindustan Tibet Highway and other similar events. Incidents of landslides were also reported from Solan, Sirmaur, Bilaspur, Hamirpur and Palampur.

Cloudburst :

Cloudbursts are sudden heavy rainstorm and its downpour. Generally, when clouds traversing pass over an area of low atmospheric pressure and temperature, vapours are condensed into raindrops, which fell on the ground by virtue of their weight. However, in mountains areas clouds are multi-layered. When one layer traversing at higher altitude enter into a zone of extremely low atmospheric pressure, then suddenly all the vapours are converted into water simultaneously. This water-column, while falling from the height, also takes the water from the clouds of other lower layers and rapidly falls on the earth. This is called cloudburst.

Most of the cloudbursts incidents take place in the Himalayan Mountains and only a few have been recorded in Extra Peninsular India. Since the major rainstorm zones have already been identified and demarcated on a national scale, there should be no reason that people continue to suffer from it. It underscores the inadequacy of our efforts in disaster mitigation.

One major recent cloudburst event occurred in Himachal Pradesh on 16 August 2003 at 2.30am at Pulia Nala, Kullu district, killing 50 laborers working at an NHPC site. Another major event occurred on the night of August 10, 2002 in Budha Kedar, Bhilangana Valley, Tehri, and Ratnali in Uttarkashi, both in Uttaranchal. It led to widespread destruction in 23 villages of Bhilanganga Valley and out of these 4 villages (namely, Marwari, Meddh, Agunda and Kot) were completely devastated. Twenty-eight persons died in these four villages. In remaining 19 villages (namely, Agar, Koti, Ragasya, Titrona, Niwalgaon, Toli, Pinswad, Urni, Genwali, Jakhna, Bhigun, Thati, Bisan, Bhaladgaon, Gomphal, Chani, Padokhan, Sirsot and Sem) though there was no casualty but all suffered from landslides, land subsidence and cracks in houses.

Major landslides of Uttarakhand:

Year	Landslide
1803	Landslides induced by massive tremor in Garhwal Himalaya: Immense destruction affecting 80% of the population
1816	Pauri Landslide
1842	Joshimath Landslide
1857	Massive landslide blocked the flow of the Mandakini river
1868	Landslide at Chamoli Garhwal blocked Alaknanda river : Swept 2 villages and killed 70 pilgrims
1880	Landslide in Nainital Town : Massive destruction and killed more than 151 persons
1893	Landslide blocked Birahi Ganga and formed an artificial lake near Gohna village in Garhwal Himalaya
1894	Breach of Gohna lake causing “Birahi Disaster” in Alaknanda valley
1906	Helang Landslide
1945	Patalganga Landslide
1963	Nainital Landslide
1963	Kaliasaur Landslide
1965	Karnaprayag Landslide
1970	Landslides formed an artificial lake in the upper catchment of Alaknanda river, 101 villages Affected, 25 buses of pilgrims Swept away, 55 persons & 142 animals died. District headquarter of Chamoli district devastated and subsequently shifted to Gopeshwar
1979	Okhimath landslide : 39 people died
1981	Uttarkashi-Kedarghati Landslide
1986	Landslides at Jakholi in Tehri Garhwal & at Devaldhar in Chamoli : 32 lives lost
1991	Gopeshwar landslide : 36 people in 6 villages died
1996	Bhimtala Landslide
1998	Massive landslides in Okhimath area formed an artificial lake blocking the course of Madhyamaheshwar river (tributary of Mandakini): 109 people died, 1908 families from 29 villages affected & 820 houses damaged

1998	Malpa landslide into river Kali: wiped out Malpa village near Dharchula in Pithoragarh, more than 300 people died
2001	Phata and Byung Gad landslides : Around 20 people killed & several houses damaged
2002	Landslides at Budhakedar and Khetgaon
2003	Varunavat Uttarkashi causing the burial of numerous buildings, hotel, and government offices located at the foot of the hill slopes.
2004	Badrinath District Chamoli sixteen people killed, 200 odd pilgrims stranded, 800 shopkeepers and 2,300 villagers trapped as cloudburst triggered massive landslides washed away nearly 200 meters of road on the Joshimath-Badrinath road cutting off Badrinath area.
2005	Govindghat, District Chamoli a cloudburst/landslide occurred in which huge quantities of debris and rock boulders were brought down along a seasonal nala. Eleven people were killed and property lost
2007	Village Baram/Sialdhar, Dharchula District Pithoragarh a landslide due to excessive rainfall resulted in 15 fatalities and loss of livestock.
2008	Amru Band total 17 people were killed
2009	Berinag-Munsiyari road District Pithoragarh forty three people died due to landslide triggered by cloud burst.
2010	Ganga-Alaknands Valley nearly 220 people died, 170 major and minor roads severely damaged.
2012	Okhimath, District Rudraprayag sixty eight people killed in the landslide, which caused extensive damages to the buildings, agricultural lands, and roads at several places.
2013	As of 16 July 2013, according to figures provided by the Government of Uttarakhand, more than 5,700 people were "presumed dead." This total included 934 local residents. Apart from 28 people died in District Pithoragarh, Bageshwar.
2015	Malpa landslide into river Kali: wiped out Malpa village near Dharchula in Pithoragarh, more than 25 people died and several Missing
2016	Bastari landslide in Tahsil Didihat, District Pithoragarh, more then 14 people died, 6 were injured and 14 people were missing. Village Naulara near toe Nachani in Tehsil Munsiyari District Pithoragarh 4 people were died.
2017	Tehsil Ghatiya Bagud and Malpa 17 people died; 07 army persons and around 30 local people missing due to landslide triggered by flash flood.
2018	Seemadwar, Dehradun 7 people died, 2 Injured, 2 houses collapsed

	69 persons died in Uttarakhand in various natural disasters such as landslides, debris falling on people, floods, flash floods and cloudburst.
2019	6 people died on 12 August after landslides in 3 villages in Chamoli district. Flooding from the Chuflagad river in Chamoli swept away two buildings.
2020	25 people were died.
2021	08 people died on October 18, 2021, 3 each in Pauri and Pithoragarh and 02 in Champawat. In October, Uttarakhand registered 45 more deaths. Of these, the highest number of deaths (28) were reported in Nainital, 6 in Almora, 8 in Champawat, 2 in Udham Singh Nagar and 1 in Bageshwar. The 2021 Uttarakhand flood, also known as the Chamoli disaster, began on 7 February 2021 Deaths: 83 and 121 missing
2022	09 people died after their car was washed away by a gushing river stream in Ramnagar of Nainital district on 8 th July morning.

Fig. 3

Forest Fire :

The youngest mountain ranges of the Himalayas have been assessed as the most vulnerable stretches of world with regard to forest fires. In 1999, forest-fires in the hills of Uttaranchal destroyed more than 3,75,000 hectares of forest. The same year, more than 450 cases of forest fire were reported in Himachal Pradesh and by May 1999, more than 80,000 hectares of forests were turned to ashes. Factors leading to a forest fire can be broadly grouped in three major categories, though in reality, a big forest fire outbreak is caused from the fractional contribution of many of these factors.

Floods & Flash Floods in Mountains :

Floods are caused by extra-ordinary intensive rainfall of longer duration. Every year floods are recorded in one part of the country or the other. The major flood-prone areas of the country are already identified, yet there is a paucity of planned systematic strategy dealing with the floods. This has resulted in massive damages in the last 50 years. This also reflects a failure at the policy level.

In the Himalayan region, flash flood is one of the major disasters which causes heavy damage to human lives, livestock's and property.

Conclusion:

The entire Himalayan region is very sensitive to natural disasters or we can say that we have inherited the disasters. We all have to live in the midst of these

calamities, we cannot go anywhere. Its solution is only pre-preparation, which is mandatory from villages to cities, towns to communities level. It is a truth that disasters are occurring definitely continuously. It is not in the power of humans to stop them, but their effects can definitely be reduced.

Skill Development Ecosystem: A Plethora of Initiatives and Opportunities

-Ragini Tewari,
Consultant Key Resource Centre-WATSAN,
Centre for Good Governance,
Dr. R.S.T. Uttarakhand Academy of Administration,
Nainital

It is now well established that the working age population in India present a tremendous opportunity by forming the major share of the population. These statistics have been time and again reiterated and reminded through various data, surveys and studies to remind of the burgeoning opportunity. It is true that India's working population/age group is one of its key strength if tapped adequately. However, in such a scenario it is the 'skilling challenge' that has to be overcome in order to leverage the demographic advantage to its full potential. While skilling and quality are a major focus of the current policies and schemes on skill development and vocational training along with the massive challenge of translating skills to employability, it is also important to note the factors of consistency, sustainability and growth in the employment generated as a result of skilling interventions.

The journey of an individual becoming more skilful and competent over a period of time is ultimately gauged by his/her efficiency in performing the allotted work. Thus, the very essence of skill development is to build efficiency to perform a task or activity proficiently. Between the building and performing lies the skill gap which has become a popular term and a common concern currently.

Even though the mandate is to train maximum numbers to be skilled, the future of jobs and decent jobs is an equally important dimension. The emphasis on skilling is made clear consistently through the importance laid on it by various important actions and interventions such as the Sustainable Development Goals (SDGs), through the institutional mechanism of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE); the National Skill Development Mission (NSDM) and its seven components (Institutional Training, Infrastructure, Convergence, Trainers, Overseas Employment, Sustainable Livelihoods and Leveraging Public infrastructure) and the National Skill Development Corporation (NSDC) etc. As the Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) is the education goal with the aim to "ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all" with Target 4.4

focusing on “increase the number of people with relevant skills for financial success” *it an SDG that brings forth the good governance parameters as well as their relation with skills and learning for all.* The goal and the target therefore directly lay emphasis on the core elements related to skill development namely: equity, quality, lifelong learning, relevance, demand and supply and ultimately financial security *while also not limiting the understanding of the term ‘skill’ in a technical and narrow way. The* Target 4.4 *also gives a way forward;* “By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship”. The *universal* importance of skills in promoting economic development, inclusive growth, reducing poverty and achieving decent jobs for all is communicated well through the Sustainable Development Goals. *In the Indian scenario,* the 'Skill India Mission' campaign majorly lays emphasis on skilling as a way forward towards growth *and the skilling ecosystem gained more momentum in the year 2015 and onwards becoming an umbrella scheme.* As a PPP model the National Skill Development Corporation (NSDC) is entrusted of promoting skill development by providing funding for vocational training initiatives while also setting up mechanisms to ensure quality.

It is important to understand the important elements in the journey between a skilling initiative and its conversion to a sustainable work with decent income. The important policy interventions in the skilling sector such as the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) 2016-2020, Udaan, Jan Shikshan Sansthan, Entrepreneurship Development Programme (EDP) under the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS), Craftsman Training Scheme (CTS) through Industrial Training Institutes (ITIs), Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP) etc. ultimately are efforts to create a stronger, brighter, resilient and a capable workforce. Primarily the focus is on creating skilling systems that match supply with demand at the same time focus on the marginalised sector. To achieve this remarkable goal, enhanced coordination at different tiers of the skilling structure has to be assured. It is of paramount importance to note that skill development initiatives are essentially meant for the marginalised to address the vulnerability quotient essentially. As noted by Gooptu “*Generating suitable employment is thus a paramount policy preoccupation to prevent a social and political upheaval, especially affecting deprived social groups as well as communities in underprivileged geographical areas, who lack the skills to enter the workforce,*

*other than in the lowest reaches of the labour market in a state of perennial economic insecurity. Skill policy is thus aimed at low-income groups with low levels of literacy, such as school dropouts” (p. 242).*¹

Further, the element of convergence across sectors in terms of skill training activities that is assured by National Skill Development Mission is a noteworthy aspect. It has led to better coordination and has been instrumental in bringing together various stakeholders. To impart quality skills, content standardization is important and thus skill framework certification systems known also known as the ‘Quality Pack’ QP is very interesting to note and a major benchmark in terms of assessment and qualification systems that gauge the quality of content in the skilling domain. Finally, efforts to enhance management and monitoring at all levels for accountability are a must to ensure a wholesome and robust skilling atmosphere.

The manner in which training and teaching is being imparted itself needs timely makeovers to keep in pace with the fast and changing times that demand upskilling continuously. Therefore, the need to change and revamp training systems itself and promote short term courses are crucial interventions. A model example of such a robust system is the World Skill Centre in Orissa. The World Skill Centre is assisted by Asian Development Bank and the Institute of Technical Education Services (ITEES) is the knowledge partner. Having a very strong institutional mechanism it also takes into account the very basic yet crucial values of ‘human centricity, discipline, integrity, teamwork and creativity’. This is not only noteworthy but also a true guiding light for other future initiatives to have the simple and core human values intact at the same time build a strong infrastructure with quality content. The backbone of skilling system being the ITIs and Polytechnic are given the due emphasis and they form the core of the World Skill Centre in Orissa. The two aspects of policy namely the content and infrastructure are ensured well through the **Intellectual** Infrastructure, **Authentic** Learning Environment and the **Emotional** Infrastructure.²

It is therefore a novel approach towards skill development and also has innovation in its very outlook towards skilling. The learning systems can be

¹ Source: Nandini Guptoo (2018) JSAD Special Issue on Skill Development in India. Journal of South Asian Development 13(3) 241–248. Retrieved from: <https://journals-sagepub-com.tiss.remotlog.com/doi/pdf/10.1177/0973174118822391>

²Source: <https://www.worldskillcenter.org/>

strengthened fully when there is a good amalgamation of values, ethics and is inclusive of all types of skilling ranging from cognitive, socio-emotional, and technical to digital skills along with rich and quality content and robust overall infrastructure. The Orissa Skill Centre has truly set an example and gained a lot of skilling momentum through its constant endeavours. It is both a best practice and an inspiration for all those involved in the strengthening of policy making and working in the skilling arena.

One of the major challenges associated with skill development programmes reaching the population in need of such programmes is the lack of awareness of skilling interventions. While numbers and data pertaining to shortage of skills, demographic development, skill training programs is often highlighted by the media, it is also to be acknowledged that ample information related to skilling initiatives is lacking. Therefore, it becomes profusely clear that the need is to conduct workshops and awareness programs at the grassroots and make use of the bottom-up model in this case. The SANKALP skill development program of the MSDE is one such initiative. However, the awareness component needs more scaling up and advancement.

The focus of the government on skilling makes it undoubtedly clear that skill development is an important agenda to achieve a strong workforce to work towards a brighter future. Along with it the focus on decent jobs, it also brings forth the crucial dimension of dignity which is an important marker of sustainable development. It is imperative to look at skills in the context of development which is sustainable, inclusive and equitable. The focus of skill development on the marginalized section particularly women, persons with disabilities and the local artisans is one of the most important aspects of the skilling discourse. The skill development ecosystem will be promising and fruitful in its due course when the amalgamation of quality, equity, matching supply to demand, generation of decent jobs and their sustainability are fully and consistently ensured.

Faith Healing in Garhwal Region of Uttarakhand

Vikas Singh
Public Health Professional



Faith Healing

Acknowledgement –

First of all, I would like to thank my field mentor Shri Harilala Madhvan whose tireless support and continued guidance made this study possible. Without his guidance and support the study could not have been possible.

I would express my gratitude to all five faith healers who allowed me to take their interviews and who shared their valuable knowledge with me viz Shri Ratan Mani Nautiyal, Shri Matvar Singh, Shantu Das, Shibba Das and Sumer Singh Panwar. I am also thankful to all the other respondents who were integral part of this study.

At last, I would also extend my respects to the temples I visited during the course of my research. For there was something magical about those temples, it transformed me from within and enabled me to perceive things as they really are without any bias or prejudice.

Executive Summary

I conducted my study in three districts of Uttarakhand namely Tehri Garhwal (Jaunpur region), Uttarkanshi (Nogaon and Purola region) and Dehradun (Jaunsar region). Respondents were mostly from SC, ST and OBC category and a few of them belonged to general category as well.

In this study 5 faith healers with different areas of specializations, with unique knowledge of faith healing methods have been interviewed thoroughly. 17 patients who took the services from faith healers as a measure to treat their ailments were also interviewed. In the course of my two months independent study on faith healing I encountered many aspects of faith healing which will be explained further in the report.

Introduction-

It is believed that treatment of human body started with no medicine but with supernatural measures. Humans have always been very close to nature since time immemorial, hence linked every event, occurrence and happening with nature which was but obvious. If things were in proper order and they were getting good amount of yields, fruits, meat, shelter and their body was healthy then it was considered blessings of the local deities and spirits. But on the contrary if they were not well, their land is struck with famine or some natural disasters came upon them, then it was certainly considered wrath of the local deities or spirits, thus started various ritualistic practices to please nature by various sacrifices. These sacrifices were of fruits, grains, animals and sometimes human sacrifice too to avoid disasters, famine and to treat ailments. “History of Indian Healing Tradition” an article states that many ailments were treated by ritualistic practices in Vedic era. Indian medical tradition, itself has been divided into two streams which are folk (it includes knowledge of local herbs, roots and different practices of faith healing) and classical (institutionalized system like Ayurveda, Sidha etc.).

Even in 21st century a vast number of people believe in faith healing and go for it. There are still many communities in India whose doctors come with feather, smoke and mantras and not stethoscope. Like Gond community in Andhara, Bhotiya in Uttarkhand etc. In “Indigenous Medicine and Health Care among Paite Tribe of Manipur” Nemianningia Guite writes about local health tradition and a significant part of the book deals with faith healing in detail. A N Narayanan Nambi and Antonio Morandi write in their book entitled ‘An Integrated View of Health and Well-being, Bridging India and Western Knowledge’ that faith healers derive their knowledge from dreams, intuitions and environment.

Similarly, Garhwal is not an exception to faith healing. Garhwal is a part of the Himalayan State Uttarkhand and has a rich tradition of faith healing so much so that even major problems like snake bite, viral fever, jaundice etc. are being treated by

faith healers. People of this place still believe in witches and they say that witches are so expert in their work that they can eat all the internal organs of a person while giving not cut to the body and eventually that person will die. They find faith healers only solution for it. These faith healers are widely respected in the region especially in rural areas.

A local journalist of Uttarkhand (The Tribune) Ajay Ramola writes in an article that priests, faith healers have played a crucial role in their traditional medicine. The knowledge of their tradition is based on teacher student system which passes one generation to another. Some intellectuals believe that wild animals have played an important role in enhancing their knowledge. Ajay also writes that when he interviewed Birsu Das from Chakrata district Dehradun, he told that his grandfather used to keep a divine stone with him which he used for the treatment of snake bite or spider bite.

A renowned writer of Uttarakhand Mr. Ratan Singh Jaunsari writes in his book “Jaunsar and Babar, Ek Sanskritik, Arthik Evam Samajik Adhyayan” that area of Jaunsar, Ravain, Babar and Jaunpur have always been under the influence of faith healing since time immemorial. He writes about how people end up losing their lives after getting stuck in the trap of faith healers. But he also writes about the maracas of temples that have treated innumerable people. Dr. Vachaspati Maithani also writes in book “Garahwal Himalaya Ke Dev Sanskriti” on faith healing.

Methodology-

It is an entirely qualitative study. I conducted in-depth interview with five faith healers and 17 patients. The entire study was based on unstructured interviews which were but conversations. I spent 4 to 6 days with each faith healer to get thorough knowledge about faith healing. I only focused on primary data which was collected by me. I extensively referred two books written by Ratan Singh Jaunsari and a book of Dr. Vachaspati to know about local customs and culture and how faith healing is a part of it.

Objectives/Answering three major questions of the study-

The study revolves around three major questions those are interlinked and are supplementary to each other (My objective was to find answers to them). Answers to these questions are based on observations, learnings and respondent's responses. These questions are following-

- I. What is the scope and role of faith healing in local healing system in the field area? Analyzed from the perspective of faith healers and their clients.
- II. How these faith healers are establishing their legitimacy?
- III. What are the major factors leading to higher demand for faith healers - even though there is development in bio-medical science, sophisticated modern technology and dissemination of modern medical systems?

My objective of this study was to look into multi ferous dimensions of faith healing and to observe aspects of it social, economic and cultural.

Findings as per three primary questions-

1. Scope and role of faith healing in local health system

There is no direct answer to this question as the responses of respondents were vague in nature. To understand role and scope of faith healing thoroughly, local health system must be understood first. Local health tradition of the area is a mix of Ayurveda and Tantra Vidhya (A supernatural way to treat ailments, although Tantra is a part of Vedic Scripture). Faith healing in the area not only includes Tantra Mantras or different sacrifices but it also includes use of local herbs, roots, wild fruits etc. And there is a wide variety of faith healers with many specializations, some are experts in casting away evil eye, some only deals with jaundice, some know the Mantra of Snake and Scorpion bite, some are specialized in treating stomach related problems etc. Therefore, a variety of ailments can be apparently treated by these faith healers. There are various methods of healing people which are explained in detail in this paper.

A tribe called Jaunsari (largely found in hilly region of Dehradun district), is one the five tribal groups of Uttarakhand that use faith healing as one of the systems of treatment. Faith healing is still a prominent system of healing in Jaunsar. Though a great shift has been witnessed in people's behavior with the commencement and improvement in health services in the area. Education has also played a significant role in making people aware about demerits of faith healings practices. The area has also been exposed to new scientific methods of treatment. Health camps like polio, RBSK, VHSNDs, growth screening, checkups etc. by Health Department and by some other charity groups are being held in area time to time. These community level health services have helped in spreading health awareness among locals. There has been significant improvement in health infrastructure and results can be seen in increased health seeking behavior. However, there is a significant gap in health service delivery

due to the lack of health and overall infrastructure in remote hilly areas and unwillingness of human resource to be posted in such areas. This gap is filled by local faith healers. People still put their faith on them, so much so that even snake bite cases are being treated by such faith healers.

But mostly people approach faith healers for minor ailments like fever, viral, fever due to shock or being frightened (sometimes women and children get frightened by mistaking bush to be a ghost, shadow, thunder bolt sound or by seeing a dead body which results in fever) etc. in such cases faith healers give them “Bhabhuti” (Chanted ash) or “Chanted water”. These chanted water and ash are also used to cast away evil spirit. Locals believe their loved ones are suffering with ailments like fever, viral or mental health related issues owing to evil spells. The people those who give Chanted water or Bhabhuti usually do not charge anything as they believe that their local Devata or God has blessed them with this power so that they can serve their people and if they charge anything or are proud of their skill then their medicine won’t work. However, there are many faith healers who charge a huge amount of money, sometimes even more than a good hospital charge. They ask for various paraphernalia, animal sacrifice etc. But if situation worsens, then people would approach health facility as last resort, though in some cases the last resort is faith healers itself.

However, it can be concluded that improvement in health services have resulted in a positive behavior change and future of faith healing is not that bright. But at the same time faith healing is still prevalent in the area as people still put more faith on the people whom they can meet on daily basis, who are from their culture and community and who are easily approachable.

2. Establishment of legitimacy by faith healers

When it comes to establishing legitimacy, faith healers are very expert in it. As already mentioned, study is mostly conducted in tribal and OBC areas of these districts. A huge part of these areas was never under British Empire (though in the year 1816 some part of Dehradun district came under British Raj while other remained in the kingdom of Garhwal under the kingship of Tehri’s King who was then considered as a representative of lord Badrinath). Hence the area remained untouched by British Raj and no advancement in terms of infrastructure, roads, education, and health etc. could take place in the area prior to independence. Therefore, area remained backward and hence was declared OBC. Since it is a hilly area so there were very few schools and that too were either in district headquarters or in cities. Same

was the condition of hospitals and health education. Mussoorie and Dehradun two major cities were under British rule therefore access to these two was not easy. Hence area remained untouched till 1947, after which it was merged into Republic of India. Therefore, faith healers and Vaidhyas were the only people to whom people could go for treatment of their illness.

Since the area belongs to STs and OBCs, so the community has been given some privileges to protect and practice their cultural practices. Under the shelter of these privileges' faith healing is being practiced in area and there is no system in place which could regulate it. Situation is such that even MLA and ministers are clients of faith healers and have an unflinching faith on them. A well known Politian of the area, on the condition of keeping his identity secret, revealed that his daughter was suffering from some mental health issue and he checked with many doctors and psychiatrists but no one could bring any improvement in her condition. Her problem, as he explained was that she would go wild at any time of day or night, behaved in a strange way, would sweat a lot and her body would shiver with fever.

This went on for two years, even though his daughter was on medication but eventually with the advice from someone he approached a Tantric faith healer who performed an old Tantric ritual in his house for 7 days and on the last day he performed his Tantric ritual nearby a water spring, where he offered some grains, pulse, a piece of cloth, bronze plate and sacrifice of a black hen. The tantric gave some ash and rice grains to the girl which she was supposed to eat in the morning and at night, he also gave her a piece of root with one "Talisman" with some instructions. The politician stated that he followed the instructions of the tantric their daughter got better in no time. In return to his service, they gave faith healer a large amount of money with grains, pulses and eatables.

Though the Tantric might have manipulated the politician, but when a known politician shares this story with others, people tend to get motivated by it and their faith-on-faith healers or Tantric gets cemented. This helps in legitimization of faith healing. Also, some of the Tantrics do use Vedic rituals to invoke certain energies but such Tantrics are very rare.

3. Major factors leading to demand for faith healers

It cannot be claimed that there is a higher demand for faith healers, however, they are a significant part of local health tradition of the area. They still have a large share of

patients. Following are the reasons why faith healers are still in demand inspite of significant advancement in modern medicine and availability of resource etc.

Lack of Health care awareness

Lack of proper education is the most prominent reasons that is keeping demand of faith healing alive. As far as literacy rate is concerned it has gone up, today a greater number of people can read and write, however as far as health awareness is concerned, there is always room for improvement. Still in many parts of these areas people link diseases with spirits, curses, God's wrath, fairy's wrath and to Ghosts. They think that since these diseases are caused by supernatural beings, they cannot be treated by an ordinary doctor. This belief is so deeply rooted that they even treat snake bites with faith healers. Although, during the course of my research I met 4 respondents who suffered snake bite, they said they did not take any medical treatment for their bite but simply went to faith healers who treated them with Mantras. This was astonishing for me but as about 75% snakes are non-venomous, so these people might have been bitten by non-venomous snakes.

Also, people are not much aware about diseases and what causes them. As far as rates of Anemia and Infant Young Child Feeding is concerned the rates are really concerning. A significant number of children are suffering with anemia, stunting and wasting and under-weight. However, instead of treating children with medical interventions or feeding practices they are being taken to faith healers.

Trust on faith healers

Trust is also a leading factor to faith healer's constant demand. As faith healers share same language and culture, and come from same society so they meet their potential patients quite often which helps in building trust. People believe in the power of faith healing and they also believe that faith healers have blessings of their local deity, so they possess powers which can treat theirs of their loved one's ailments. Some faith healers have been practicing faith healing for many generations. Mostly the knowledge of faith healing is passed on to male member of the family and the legacy goes on.

Also, as the terrain is hilly and remote, so many of the times it so happens that some unqualified doctors set up their clinics in rural helmets. They call them Bengali Doctors (sometimes these people don't even have degree). People approach these unqualified doctors with ailments, though they can treat the minor ailments like fever

and minor wound but they are not capable of treating serious ailments so most of the time they give wrong medicines which further deteriorates the condition of patient. In such cases patients would eventually go to Mussoorie or Dehradun for treatment or would directly approach faith healer. And if somehow their ailments get treated by faith healers, then their faith in them increases.

Economically viable

Treatment by faith healing is much cheaper than by modern medicine which includes doctor's fees, medicine cost, travel cost etc. Although government hospitals are economically viable and charge nominal hospital fees but most of the time doctors prescribe medicine from outside which are again costly. Many doctors in government hospitals in cities like Dehradun don't encourage people to buy generic medicines from Government of India's Jan Aushdhi Kendra. Therefore, a disease might shake the whole economy of the family. As per WHO report more than 55 million people in India go into poverty due to household out of pocket expenditure on health services. Most of the out-of-pocket expenditure on health services goes into outpatient care and medicines.

Therefore, if people in these areas get fever or have any minor ailment, they go to faith healer and get chanted ash or chanted water from them. Chanted water and ash is given for free from these faith healers. As far as diseases like jaundice is concerned almost everyone gets their jaundice treated by faith healers, and again these faith healers' charge nothing for their treatment. While treatment for jaundice in hospital may cost them significantly. There are many other ailments for which people approach faith healers first and if they see no improvement then as a last resort they go for medical treatment.

However, some faith healers, mostly those who practice Tantra, demands their clients for animal sacrifice, certain items, metals and other paraphernalia etc. this sometimes costs them even more than the cost they would have otherwise spent for good medical treatment. But now days many people have stopped going to these Tantrics.

Geographical constraints

The terrain is hilly, some villages are located at the altitude as high as 6000 to 7000 feet sea level. Many villages do not have road connectivity. And during rainy seasons even nearby main roads connecting to cities like Mussoorie and Dehradun

gets blocked due to landslide. It may take days and weeks before roads are operational. So due to lack of road infrastructure and lack of communication with major cities, people usually prefer going to faith healers for primary treatment of their ailments. Since terrain is hilly even Doctors and medical staff avoid to get posted in such areas.

Culturally bound

Faith healing has been an integral part of their culture. For many centuries faith healers have been doctors of these areas, along with practitioners of traditional medicines known as Vaidas. Many of these faith healers claim that local deity takes charge of their body and it's with their power they treat the ailments. People in these areas are very superstitious in nature. They still believe on dark spell, dark magic and existence of witches. In addition to this people have unflinching and unalloyed faith on their local Gods whom they call Mahasu, Botha, Pawasi and Chalda. They believe that these four "Mahasu Brothers" can treat everything and it is evident in their local songs in which they thank Mahasu for keeping them healthy and treating their disease. Jaunsari people have a strange old scripture that is written in a language which a common man can barely understand. This book includes many methods of faith healing and pleasing the deities. The book is regarded as very sacred. People not only approach their local Gods for treatment of their ailments but also for justice.

Faith healers' responses-

In this study I interviewed five faith healers to know different aspects of faith healing, their perspectives and the methods they use to treat their patients etc. Part of the same is summarized below.

1. Ratanmani Nautiyal

Ratanmani is 77 years old educated Vaidya who also practices faith healing. He is from Kudaun, a village in Jaunpur block of Tehri Garhwal. He belongs to a Brahmin family and also is priest at his village and nearby village's deity. He is a Vaidya therefore he treats almost every disease. He mostly uses local herbs, medicinal plants, roots of some bushes which carry medicinal quality etc. but sometimes he also uses Mantras for treatment. He charges 100 rupees as his prescription fees; he also charges extra for his medicines (rates are nominal). He has a good number of ever-growing clients. He claims that most of the people come to him after they have already tried allopathic medicines. As per his claims he treats the ailments which even

doctor could not treat. When I inquired more about faith healing, he told me that being a Brahmin he knows some Mantras and rituals which can treat disease like mental depression, weakness, constant body pain, evil eye which results in injuries etc.

However, He believes that now day's medicines are more effective and powerful than Mantras due to the absence of efficient Mantra chanters.

2. Mat war Singh Rawat

Mat war Singh Rawat is a 76 years old man. He belongs to Dwargrah village of Tehri Garhwal district. He is Kshtriya by birth. He was a post master in his young age and resigned the job to become Gram Pradhan. He has good knowledge of the area in terms of its history, cultural practices, festivals, tradition, local flora fauna etc. And because of his vast knowledge of the area, he used to be invited as guest speaker by well-known institutions of Mussoorie to give lecture on Garhwal and Uttarakhand history, culture and issues related to Uttarakhand etc.

He gives chanted water and "Bhabhut" to people suffering with minor fevers, body ache, panics and shocks. To get chanted water a person has to bring a glass of water with "Dub Ghas" which is a sacred grass that is also used in fire sacrifices. He mixes some "Ganga Jal" water of holy Ganges and "Gow Mutra" cow urine in that water and then stirs the grass in water slowly with chanting some indistinct mantras in his mouth. He does it for five minutes then gives it to the patient, instructs him/her not to put the glass of water down on the floor but sprinkle it on the body. However, he also instructs them that if their fever do not subside then visit the doctor. For making "Bhabhut" he chants "Hanuman Chalisa" and some other mantras. Bhabhut is meant to be applied on body. He charges nothing for his remedies.

When I asked him about his Mantras, he revealed that he had learnt the water chanting Mantras from his maternal uncle who was the only person in that village to know these Mantras, since he did not have any children hence, he passed his legacy to his nephew. But he told me that in actuality he had forgotten the whole mantra years ago as it was a long prayer and remembers only some part of it. I was astonished to hear it, so, asked him about its effects on patients. For this he related that he only treats minor ailments, and if there is something serious, he sends the patients to Doctor without delay. However, he believes the Mantras do carry certain energies which helps in the process of healing. He said that people believe that due to some evil eye they are ill and the chanted water or ash can protect them. And once they are mentally satisfied, psychology and faith play a crucial role and their mind makes their

body well. He said he doesn't reveal it to them, because if he does so then people may approach another faith healer who may cheat them and charge them a heavy amount of money.

He concluded that as per his experiences in these years, he believes that not only medicine treats the person but a firm faith, trust, positive thinking also helps in healing process. He related that a mentally depressed person loses his skin color, black patches appear on his/her face, body gets weak and loses weights etc. but a positive wave, positive thinking and a firm belief can get them back to their normal condition.

3. Shibba Das

Shibba Das is a 50 years old man from Barkot region of Uttarkashi district. He is illiterate and belongs to a backward caste. He is a Tantric faith healer who relates almost every disease and problem with ghosts, witches, fairies, dark magic and curse etc.

I went to meet him in his house and he had a considerably big house. I asked him about Tantra techniques, how he examines and gets to know that a particular person is cursed by a particular person's curse or have been affected by ghosts or by witch craft etc. He said he is a devotee of "Devi" goddess and "Devi" helps him know the cause of the disease or problem. He said that he also calls upon spirits who help him in process. He showed an old book to me which I could not read though it was written in Dev Nagari script. He makes people see things in oil pots. At first, to examines, he uses some pulse and rice grains and scatters it on a plate and asks questions while keeping on throwing it on plate, he calculates the position of grains and concludes the cause of problem. He uses many Tantric methods in order to heal his clients. After knowing the reason of the disease, he performs a Tantric worship in which most of the time animal sacrifice with other paraphernalia is needed. He also charges a large amount of money from his patients.

4. Sumer Singh Panwar

Sumer Singh Panwar is a 66 years old shop keeper in Jaunsar, Dehradun district. He is a well-known faith healer in the area and treats jaundice. He also belongs to Kshtriya community. People from all over Jaunsar, Bavar and Jaunpur approach him for jaundice treatment. He charges no money for his treatments but treats his patients only on Fridays and Sundays. These are the days he says his Mantra works. He says he learnt it from his father who used to be the well-known jaundice

healer in the area. He adds when a person approaches him with jaundice, he would make him/her sit on a wooden stool and takes out his bunch of local grass/bush and would role it around patient's body many times along with Mantra chanting. He gives no medicine to the patient but he advises him/her not to take food which are hot in nature. The person is also restricted from eating oily and spicy food. He added that a person has to visit him at least three times to get fully treated. In another method he pours some oil in a plate and roles a poisonous grass on patient's head, that's how he treats his patients.

5. Shantu Das

Shantu Das is a 59 years old man from Jaunpur block of Tehri Garhwal, who calls himself drummer of God. He is a faith healer and deals with various problems like fever, body pain, fevers in infants, evil eye, dark magic etc: He also treats snake bites. However, these days, people take snake bite cases to hospitals and very few cases are taken to faith healers due to health awareness. But as I came to know from people most of the snake bite patients taken to hospital do not survive as hospitals are very far. Hence, some people approach faith healers. When a patient with snake bite is taken to Shantu Das, he at first ties a cloth a few inches above the wound to prevent poison reaching other parts body. Then he puts him in big basket made up of bamboo. Once patient is in bamboo basket no one is allowed to touch him. Patient is given large quantities of cow ghee to drink. Shantu Das uses mantras and eagle feather which he would role on patient's body to remove poison from his body.

Shantu Das told me that most of the time he is successful in treating the patients, but sometimes it so happens that people bring an already dead person for treatment. He also added that if it's in the destiny of a person to die then he would definitely die, but once a person is brought to him, he would never let that person die. Shantu Das charges nothing for snake bite cases but for other ailments he would accept the fee.

Summarized responses from the patients

I interviewed 17 people who at some point in their lives had tried faith healing for theirs or their loved one's treatment. Following is the summary and analysis of their responses –

Responses which I got from people were not same. For some people faith healing worked, while, some do believe on it but they prefer approaching hospitals

first. Some were cheated by faith healers (mostly Tantrics) and lost significant amount money while the condition of patient further deteriorated. Such was the case with Hukum Singh Kaintura. He is a farmer with no regular income. He shared that about 11 years back his daughter committed suicide by drinking poison. And right after that another daughter caught some serious fever. He said he went to a local doctor but his daughter's condition did not improve. Therefore, he was advised by villagers and relatives to approach a faith healer as they doubted that some black magic has been done against his family and if some remedy is not done for it then consequences might be even more adverse. He approached one of the Tantrics, who asked him to do animal sacrifices many times and each time charged a considerable amount of money. Though, the ritual went for many months but no improvement was seen in the condition of his daughter, he went to another faith healer only to get ransacked again. Since he came from economically unprivileged section, so he had to borrow a big amount of money from his relatives and friends in order to perform these occult rituals and it took him years to pay back debts.

In one other case one of the respondents shared that his father had a paralysis attack, after checking with doctor and seeing no visible improvement they approach not one, but many faith healers or Tantrics. However, there was no improvement in the condition of his father and eventually his father died. He also had to lose a big amount of money in Tantric rites. There were many such cases in which Tantric faith healers ransacked innocent people.

However, on the other hand some respondents said that their diseases were treated by faith healers, while doctors had failed to treat or even failed to diagnose the disease. Vikram Singh Rawat from Barkot Uttarkashi district. Who is well-educated guy and has worked under a renowned lawyer said that once his one-year-old girl got seriously ill, they took her to Mussoorie and Dehradun for treatment, but no doctor was able to diagnose her disease. Doctors even said that girl was perfectly fine, with appropriate growth as per her age, weight and height. Vikram shared that his daughter would turn blue, her whole body would get cold and she would go unconscious. He said he would put Bhagwat Gita on her head and read out Hanuman Chalisa that would give her some relief and bring her back to consciousness. He eventually called upon Shantu Das who gave him a Talisman and chanted ash. He would apply the ash on girl's forehead and had tied the Talisman around girl's neck. Vikram added that on

7th day his daughter became perfectly fine. Many respondents also shared how their ailments got healed with chanted water and Bhabhuti.

Temple Healing

Temple healing is also prevalent in area. They have their local gods whom they call Chalda, Bhotha, Pabasik, Basik, Mahsu and many others. All these deities have their own ancient temples. The famous temples in area are Hanol, Basoi, Laksiyar, Lakhward, Raghunath etc. People have enormous faith in these deities so much so that they settle their land, property, jewelry and other legal disputes with the help of local deity only. Not only disputes but these temples also help in treating diseases which apparently doctors failed to treat. People with mental health issues, pregnancy problems, skin diseases, leprosy etc. visit temples for their remedy. They often take vow that if their desire is fulfilled, they would offer a certain number of sheep, gold coins or some other gift as a tribute to temple deity. Many of locals I talked to said that these deities are very powerful, as they are Ganas of Lord Shiva or personal associates of Lord Shiva. They have power to render justice, fulfill any desire and treat any disease. Locals keep temple Prasadam as medicine.

In addition to miracles of local deities, a temple of Bhavani Devi is also very famous for fulfilling desires. Couples with issues in child bearing visit the temple and many of them have shared that they were bestowed with a child by Goddess Bhavani. One of my respondents also shared that by the mercy of Goddess Bhavan they begot a child after 10 years of their marriage. The popularity of the temple can be understood with the fact that WWE wrestler The Great Khali also visits the temple whenever he comes to India.

Conclusion and Recommendations –

Health and Nutrition status of women and children in Uttarakhand

The research has been conducted in hilly regions of these districts where due to geographical constrains health infrastructure is not as good as it is in plains or cities. Although, Government has ensured that primary health centers and sub-centers are built in remotest areas of the district but due to less population density in hilly regions people have to cross miles before reaching to these centers, due to which State did not witness expected improvement in health and nutrition indicators as evident in data below –

Following are health and nutrition indicators of Uttarakhand as per NFHS-5 report–

Stunting	27
Wasting	13.2
Severe Wasting	4.7
Under-weight	21
Over-weight	4.1
BF within one hour	41.3
Exclusive BF	52.5
6-8 Month CF	50.6
6-23 Months Total Children receiving Adequate Diet	12.5
6-59 Months Anemic Children	58.8
PW (15-49) Anemic	46.4
All (15-49 yrs) Women Anemic	42.6
All (15-19 yrs) Women Anemic	40.9
180 IFA consumption by mother during Pregnancy	7.2
9-59 Months Vitamin A Dose	53.7
Mothers who at least 4 antenatal check-ups	61.8
Neonatal mortality rate	32.4
Infant mortality rate	39.1
Under-five mortality rate	45.6

As far as NFHS-5 data is concerned neonatal mortality that was 28 in last NFHS-4 survey has now increased to 32 children, while data for IMR and U5MR remained same. As far as infant young child feeding or IYCF practices are concerned only 12.5% children are able to receive adequate diet while only 41% children were able to receive breastfeeding within one hour of their birth. 27% children in State are stunted while over 13% are wasted. As far as anemia is concerned around 59% 6-59 months children are anemic while over 46% pregnant women are anemic. Although, high prevalence of anemia in pregnant women, only 7.2% mothers were able to consume 180 IFA tablets during their pregnancy. There is also a significant gap between rural and urban data. In urban areas data shows better numbers as compared to rural data.

Specially, data for RMNCH+A has to be improved as it determines the fate of current and future generations. If women, children and adolescents are reaching out to these faith healers or Tantrics, instead of health care centers for treatment, then it may not only impact their health status but can also cause other conditions like anemia, malnutrition etc. which may further result in maternal, infant, neonatal or under-5 mortality. In villages of hills, it has been observed that women usually become

anemic, especially during pregnancy, as consumption of iron rich diet and IFA tablets is low among these women. Due to anemia women become weak, pale and develop symptoms like shortness of breath, irregular heartbeats, chest pain, dizziness etc. People usually take this condition to be caused by some evil eye or black magic. Hence, they are plundered by the Tantrics, same is the case with malnourished children. During the series of my interviews, I came to know that in the time of cholera instead of going to doctors (as hospitals were usually far), the whole village would approach faith healers, especially Tantrics, hence many children and adults would die. However, when these people approached their local deities with the same problem they were miraculously cured.

As Uttarakhand has been known as Devbhumi since thousands of years. One can find mentions of Uttarakhand (Kedarkhand) in various Puranas, ancient historical texts like Ramayana and Mahabharat etc. It's the same place from where Lord Hanuman had procured Sanjivani herb that brought back Lord Laxman into consciousness. Thousands of medicinal herbs are found in valleys and hills of Uttarakhand that can treat many diseases. Locals know the use of these herbs and plants. Many of the herbs used in Ayurvedic medicine are procured from these mountains. As mentioned previously that many faith healers not only use Mantras or rituals to treat their patients but they also use local herbs, roots, plant leaves etc. which might have medicinal potencies that might help in treatment. While there are faith healers those who only practice Tantric rituals for healings their patients. Most of the Tantrics are swindlers. However, there are many faith healers who seem to be helping their community.

Although faith healing should not be promoted among rural communities as it might lead people to superstitions and can affect health status of the community as whole. However, there is a need to conduct more in-depth study on the subject matter. Studies have established that Mantras do have powers which can heal a person both mentally and physically, in fact Mantras are also part of Ayurvedic healing. Although Tantra is also a part of Atharva Veda but in modern times the science of Tantra is somehow lost, the so called Tantric who practice Tantra, most of them are frauds and have not read anything about Tantric Agamas Shastras. Many of the Tantric are usually illiterates in the area, but because they are expert at influencing people, many people would still approach them. Therefore, there is an urgent need for government to make people aware about public health services which they are entitled to. Though

faith healing should not be endorsed but people like Matvar Singh and Ratan Mani are playing a crucial role in saving people's time and money. There are still many faith healers who charge nothing from their patients and many people would see positive effects of their treatment. There are pros and cons of faith healing but allopathy or modern medicine also has its pros and cons.

Thus, faith healing is not something as clear as black and white but there are many shades of grey to it. While temple healing and healing of minor ailments from Mantras seems to work, may be due to placebo effect. However, because Tantra as science is almost lost now, therefore, community has to be made aware as to not to approach Tantrics or black magic practitioners for treatments of their diseases or for the solution of any other issue. In earlier days faith healers along with Vaidyas or traditional healers used to get a fixed amount of grains after every harvest. Now a days Tantric healers charge a huge sum of money, people even plunge into poverty due to high fees of Tantrics. However, there is a need of an in-depth study on faith healing, Tantra healing, Temple healing and traditional healing with Mantras and herbs, as these all cannot be put in the same basket.

References-

- Antonio Morandi, A N Narayanan “An Integrated view of Health and Well-being bridging India and Western Knowledge”. Chapter 7 “Health and well-being in Indian local health tradition”. Springer Dordrecht Heidelberg New York.
- Upinder Singh, Nayanjot Lahiri, Ancient India: New Research, Oxford University Press, India 2010.
- Zysk, K. Medicine in the Veda: Religious healing in the Veda Motilal Banarasisdas, Delhi 1996.
- Nemthianngai Guite “Indigenous Medicine and Health Care among Paite Tribe of Manipur”. Concept Publishing Company PVT. LTD. New Delhi – 110059.
- Ajay Ramola, “Bountiful cures in Good Shepherd's own land” The Tribune Uttarakhand Community. July 27 2015
- Unnikrishnan E, “Materia Medica of the Local Health Tradition of Payyarnnur”, Centre for Development Studies, Kerala Research Programme on Local Level Development, Thiruvananthapuram. 2004.
- Dr. Larry Culliford, “History of Indian Healing Tradition, Science and society.

- Dr. Vachspati Maithani, “Garhwal Himalaya Ki Dev Sanskriti” Gandhi Hindustani Sabha Sanidhi, Rajghat Delhi. 2004
- Ratan Singh Jaunsari, “Jaunasar Babar, Ik Sanskritik Avam Samajik Adhayann”, Geetanjali Press Dehradun. 2006
- National Family Health Survey, 4 & 5, India

Links which helped me in my study

- <http://www.cds.ac.in/krpcds/publication/downloads/80.pdf>
- http://www.ijph.in/temp/IndianJPublicHealth574212-1426169_035741.pdf
- <http://www.tribuneindia.com/news/uttarakhand/bountiful-cures-in-good-shepherd-s-own-land/111697.html>
- <https://www.ncbs.res.in/HistoryScienceSociety/content/overview-indian-healing-traditions>

बेरोजगारी एवं पलायन में न्यूनता लाने का एक छोटा सा प्रयास

कैलाश चन्द्र भट्ट ,
सीनियर सलाहकार/टीम लीडर
जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई
ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, अल्मोड़ा

वर्तमान समय में बेरोजगारी एवं पलायन एक गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है। ग्राम हों या शहर बेरोजगारी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पलायन भी एक प्रमुख समस्या का रूप ले चुका है। ग्राम एवं छोटे शहरों से युवा वर्ग रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर दौड़ लगा रहा है। हांलाकि कई तरह की योजनाओं के माध्यम से इस स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन वास्तविकता कुछ और ही प्रतीत होती है।

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति-UGVS द्वारा संचालित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2015 गठित उज्ज्वल स्वायत्त सहकारिता, कोसी द्वारा अल्मोड़ा जनपद में हवालबाग विकास खण्ड के कुल 10 ग्रामों में 46 उत्पादक/असहाय उत्पादक समूहों के कुल 520 सदस्यों के साथ परियोजना गतिविधियों का सम्पादन किया जा रहा है। सहकारिता द्वारा अपनी सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तता के लिए विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से अपने सदस्यों को आंशिक तौर पर रोजगार उपलब्ध करवाने का सफल प्रयास किया गया है।

सहकारिता की आर्थिक गतिविधियों की ओर यदि नज़र डाली जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सहकारिता आर्थिक सशक्तता की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। वर्तमान में सहकारिता की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां पशु पोषक आहार, टेक होम राशन, एक पिक अप, एक टैक्सी वाहन, हिलांस गिफ्ट पैक एवं विभिन्न मौसमी व्यवसाय हैं। सहकारिता की आर्थिक सशक्तता का अंदाजा लगाने के लिए रु.11,84,850.00 का मासिक टर्न ओवर एवं लगभग 1,39,900.00 का लाभ का होना ही पर्याप्त है। वर्ष 2020-21 में अपने कुल 520 शेयर धारकों को कुल रु.3,38,000.00 (रु. तीन लाख अड़तीस हजार मात्र) का लाभांश वितरित किया है। सहकारिता द्वारा वर्तमान में कुल 18 (स्थायी एवं अस्थायी रोजगार) लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है।

सहकारिता द्वारा वर्ष 2015 में अपने गठन के साथ ही अपनी आर्थिक सशक्तता पर अधिक ध्यान दिया। सहकारिता संचालक मण्डल सदस्यों के पूर्व अनुभव, परियोजना सहयोग आदि के कारण वर्तमान में सफलता के साथ आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं।

सहकारिता को आर्थिक गतिविधियों को आरम्भ करने में प्रारम्भिक चरण में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा:

- टेक होम राशन गतिविधि हेतु निवेश हेतु धनराशि।
- सरकारी विभाग के साथ सामन्जस्य।
- गुणवत्ता एवं ससमय आपूर्ति।

- सदस्यों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु प्राथमिकता को तय करना।
- व्यावसायिक स्तर पर गतिविधि हेतु पशुपालकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना।
- वाहन गतिविधि हेतु वाहन संचालन अनुभव, कुशल एवं ईमानदार वाहन चालक का चयन।
- हिलांस गिफ्ट पैक तैयार करने हेतु तकनीकी जानकारी का आभाव।
- मौसमी गतिविधियों के संचालन हेतु समूह सदस्यों को विश्वास में लेना।
- समस्त व्यावसायिक गतिविधियों का लेखा जोखा एवं प्रबन्धन।

व्यावसायिक गतिविधियों के सम्पादन से पूर्व सहकारिता के पास कई प्रकार की चुनौतियां थीं। कतिपय चुनौतियां तो व्यवसाय आरम्भ करने से पूर्व कदम को पीछे खींचने के लिए मजबूर कर रही थीं। इसे सहकारिता सदस्यों का आत्मविश्वास एवं परियोजना का सहयोग ही कहना होगा जिसके कारण वर्तमान में सहकारिता सशक्तता की ओर अग्रसर है।

सहकारिता की विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में टेक होम राशन एक प्रमुख गतिविधि है। इस गतिविधि के कारण सहकारिता मासिक रूप से अच्छा लाभ अर्जित कर रही है। गतिविधि को आरम्भ करने हेतु सहकारिता को अधिक मात्रा में निवेश की व्यवस्था करनी थी। उक्त व्यवस्था परियोजना सहयोग से प्राप्त धनराशि, व्यावसाय से हुए लाभ एवं शेयर धनराशि से किया गया। इस प्रकार सहकारिता ने बाल विकास विभाग, अल्मोड़ा के साथ एक अनुबंध के तहत कुल 198 आगनबाड़ी केन्द्रों में टेक होम राशन की आपूर्ति से आरम्भ की एवं वर्तमान में भी यह आपूर्ति सतत रूप की जा रही है। इस गतिविधि के अन्तर्गत गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं बच्चों (अतिकुपोषित साहित) को नियमानुसार चना, नमक, किशमिश, मूंग दाल, भुना चना आदि उपलब्ध करवाया जाता है। सहकारिता द्वारा टेक होम राशन के अन्तर्गत किया जाने वाले कुल रू. 7,17,000.00 का मासिक व्यवसाय करते हुए कुल रू. 91,000.00 का लाभ अर्जित किया जा रहा है।

आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर सहकारिता के कदम मात्र टेक होम राशन गतिविधि तक ही समिति नहीं रहे वरन् स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को प्रतिमाह 130 बैग पशुपोषक आहार एवं लगभग 700 किग्रा. चोकर को हल्दानी से क्रय कर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस गतिविधि में कुल रू. 78,350.00 निवेश करते हुए कुल रू. 10,000.00 का लाभ अर्जित किया जा रहा है। इस गतिविधि के दौरान भी अस्थायी रूप से स्थानीय महिलाओं को सूक्ष्म रोजगार का अवसर प्राप्त होता है।

सहकारिता द्वारा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों एवं किराये पर माल ढुलान करने के लिए एक पिक अप माल वाहक वाहन के माध्यम से भी आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा है। इस वाहन के माध्यम से टेक होम राशन आपूर्ति को ससमय करने में सहयोग मिलता है साथ अन्य कार्यदिवस स्थानीय स्तर पर किराये पर दिया जाता है।

सहकारिता को भार वाहन पिकअप से प्रतिमाह कुल रू. 28,000.00 की आमदनी प्राप्त हो रही है। बैंक ऋण की किस्त देने के पश्चात् कुल रू. 3,500.00 की शुद्ध आमदनी प्राप्त होती है।

सहकारिता एवं विभिन्न रेखीय विभागों के मध्य निष्पादित अनुबंध के तहत सहकारिता द्वारा 03 वर्ष के लिए जनपद अल्मोड़ा में 'मोबाईल एग्रोक्लीनिक वैन' हेतु एक वैन को कृषि विभाग को उपलब्ध करवाया थी। पूर्व अनुबंध

की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् विभाग द्वारा पुनः 2 वर्ष के लिए अनुबंध को बढ़ाया जा चुका है। इस अनुबंध के तहत सहकारिता को प्रतिमाह रु. 25,000.00 बतौर वाहन किराया आय प्राप्त हो रही है। इससे सहकारिता को एक अतिरिक्त आय एवं सरकारी विभागों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है।

सहकारिता द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्तता प्रदान करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा है। सहकारिता द्वारा एक Tough Utility Vehicle -TUV को क्रय कर उक्त को परियोजना की जिला इकाई में अनुबंध के आधार पर किराये पर लगाया गया है। इससे प्रतिमाह रु. 26,500.00 की शुद्ध आय प्राप्त हो रही है।

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर सहकारिता द्वारा मासिक रूप से रु.11,84,850.00 से अधिक का मासिक टर्न ओवर करते हुए रु.1,39,900.00 का लाभ अर्जित किया जा रहा है जो अपने आप में एक उपलब्धि ही है।

सहकारिता की आर्थिक सशक्तता का लाभ समुदाय को प्राप्त हो रहा है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सहकारिता द्वारा सृजित रोजगार से देखा जा सकता है। वर्तमान में सहकारिता द्वारा कुल 20 लोगों को रोजगार प्रदान (7 स्थायी एवं 13 अस्थायी) किया गया है। मासिक रूप से विभिन्न प्रकार के कार्मिकों को कुल रु. 77,500.00 बतौर मानदेय उपलब्ध करवायी जा रही है।

सहकारिता द्वारा लाभांश वितरण से शेयर धारकों को जहां लाभ प्राप्त हुआ है वहीं दूसरी ओर उनका सहकारिता के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। इससे सहकारिता सदस्यों की विभिन्न गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने में भी सहयोग प्राप्त होगा।

सहकारिता द्वारा वर्ष 2021-22 में अपने 520 शेयर सदस्यों को औसतन रु. 650.00 प्रति सदस्य लाभांश देते हुए कुल रु.3,38,000.00 बतौर लाभांश वितरित किया गया है।

उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त सहकारिता द्वारा हिलांस गिफ्ट पैक गतिविधि नाम से भी एक व्यवसायिक गतिविधि को आरम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत Spice Gift Pack, Deepawali Gift Pack, Cosmetic Gift Pack, Stationery Gift Pack, Herbal Tea Gift Pack, Agro Processing Product Gift Pack शामिल किये गये हैं। सहकारिता द्वारा छोटे एवं बड़े आकार के कुल 2122 गिफ्ट पैक को कैबिनेट बैठक, अल्मोड़ा, मुख्यमंत्री कार्यालय, देहरादून, निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली, गैस ऑथरिटी ऑफ इण्डिया लिमि., नोयेडा, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, अल्मोड़ा/देहरादून, जिला निर्वाचन आयोग, अल्मोड़ा, मुख्य विकास अधिकारी, जनपद अल्मोड़ा, मुख्य विकास अधिकारी, जनपद अल्मोड़ा, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी, ओ.एन.जी.सी., ग्राफिक एरा, देहरादून को उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रकार देखा जाय तो वर्तमान तक सहकारिता द्वारा लगभग रु. 30,00,000.00 धनराशि के गिफ्ट पैक का व्यवसाय किया जा चुका है। यह गतिविधि सहकारिता के लिए अत्यधिक लाभप्रद साबित हो रही है, साथ ही इसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को उचित मूल्य एवं बाजार भी उपलब्ध हो रहा है। गिफ्ट पैक को तैयार करने में कार्यरत महिलाओं को रु.450.00 प्रति पैक/प्रति महिला मेहनताना उपलब्ध करवाया जाता है।

पर्वतीय क्षेत्रों से होते पलायन एवं वर्तमान बेरोजगारी के परिदृश्य में सहकारिता द्वारा इतनी न्यून अवधि में इतने अधिक रोजगार के अवसरों को उपलब्ध करवाना अपने में एक सफलता कहा जा सकता है।

सहकारिता द्वारा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ को अपने भविष्य एवं अन्य आगामी सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखा है, साथ ही अपने शेयर धारकों को उक्त लाभ का एक भाग लाभांश के रूप में प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाया जाता है।

सहकारिता की इस सफलता के पीछे संचालक मण्डल की जागरूकता स्पष्टतः झलकती है। सहकारिता की उपलब्धि यह सिद्ध करती है कि किसी लक्ष्य को हासिल करने की सोच ही काफी नहीं है वरन् मेहनत एवं त्याग भी नितान्त आवश्यक है।

गढ़वाल उत्तराखंड की लोक संस्कृति के संवाहक लोकगीत

पद्मश्री डॉ. माधुरी बड़थवाल
लोक संस्कृति संवाहिका।

हिमालय की उपकंठ में बसा हुआ उत्तराखंड, भारतीय संस्कृति का विशिष्ट भूभाग उत्तराखंड, जो महाराजा भरत की जन्मस्थली और भारत भूमि का अभिन्न अंग है। इस वसुन्धरा के एक भाग को अलंकृत करता गढ़वाल। अलकनन्दा, भागीरथी, यमुना, मंदाकिनी, टौंस, धौली, नयार आदि नदियाँ जिस भूभाग को अपने अमृत जल से सिंचित करती है। इन्हीं नदी द्रोणियों से बना हुआ है यह श्रीबद्री-केदारखंड, जहाँ से कैलाश मानसरोवर का प्राचीन मार्ग था। यह क्षेत्र भारतीय धार्मिक कल्पना में सदैव पावन पुनीत क्षेत्र रहा है और यही अवधारणा रही है कि पग-पग पर यहाँ देवताओं का वास है। महाकवि कालिदास ने गढ़वाल के सौन्दर्य और शान्त सुरभियुक्त वातावरण से मुग्ध होकर इसे देवभूमि की संज्ञा दी थी। पाली साहित्य में इसको चुल्ल हिमवन्त कहा गया है। यही गंगा यमुना का उद्गम स्थल गढ़वाल अनेक सांस्कृतिक समन्वय व ऐतिहासिक परम्पराओं से ओत-प्रोत है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ का हर प्राणी पूर्ण रूपेण आध्यात्म और प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है, अतः ये स्वभाव से बहुत सीधे और भावुक हैं, इसीलिए यहाँ के अधिकतर गायक, वादक एवं नर्तक जन्म से ही आशु कवि भी होते हैं। जिस प्रकार आदि कवि का नाद-निनाद स्वयं काव्य बन कर प्रस्फुटित हुआ था उसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति के मानव सभ्यता के बाद, शैल पुत्र-पुत्रियों के मन के संवेदनशील उद्गारों का निष्पादन प्रसादमयी लोकगीतों की धारा प्रवाहित करती है। स्वर, लय, छन्द में समृद्ध हैं गढ़वाल के लोकगीत। इस क्षेत्र विशेष का सम्बन्ध सम्पूर्ण भारत से बना हुआ है। महाभारत के अनुसार बद्रीकाश्रम में भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन ने नर और नारायण के रूप में तपस्या की थी। नरों के नारायण भगवान विष्णु जिनके आराध्य हैं वे वैष्णव इस तपस्थली को पुण्यधाम मानते हैं। भगवान शंकर की तो ये पवित्रभूमि है ही, इसलिए केदारखंड के स्वामी का केदारनाथ धाम शैवों का पुण्यधाम भी है। हिमवन्त की पुत्री पार्वती की जन्म स्थली होने से केदारखंड अर्थात् गढ़वाल से शाक्तों का देवतुल्य पूजनीय सम्बंध प्राचीन काल से ही रहा है। सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का भी अटूट सम्बन्ध पुराने समय से रहा है। इसीलिए यहाँ की लोक संस्कृति में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है और संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं लोकगीत। लोकगीतों में ही संस्कृति जीवन्त होती है। गढ़वाल जहाँ आध्यात्म और प्रकृति का अनूठा संगम है, जिसका प्रभाव यहाँ की लोक संस्कृति में रचा बसा है। परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल उदीप्त होने वाले भाव जो स्वयंभू होते हैं, जब स्वयं ही शब्दों द्वारा निसृत हो जाते हैं तो काव्य बन जाते हैं। इन्हीं काव्य रचनाओं का स्वर मिश्रित रूप, गीत कहलाता है।

गढ़वाली लोकगीतों का परिचय देने से पूर्व यह ज्ञात करना आवश्यक जान पड़ता है कि लोकगीत क्या हैं ? लोक शब्द को लेकर विद्वानों में अनेक मत हैं। लोक शब्द के एक अर्थ में "स्वतः ज्ञात है, वन्य विभूति है वन्य औषधियों का अक्षय आगार है, वनस्पतियों का अक्षय कोष है। नाना विध, दिव्य रंग, गंध, रूप और दीप्ति का एक सरल सुगन्धित नैवेद्य है, एक ऋतु अनुष्ठान है, एक सहज उद्यापन है"। विद्वानों के एक और अर्थ में "लोक है सुगन्धित संवेदनाओं का मानसरोवर"। वाणेश्वरी-डॉ. चंद्रशेखर के अनुसार "स्वप्नों आकांक्षाओं के शत्-शत् कमलों का केसरी किंजल्क-पराग से विभूषित शुभ लालिम नीले कमलों का अत्यन्त विस्तार। एक किरण रंजित वैभव और लोक जीवन। लोक जीवन है निरन्तर मानसून की वर्षा, निरन्तर हिमपात, निरन्तर हिम विगलन, निरन्तर जल श्रवण,

निरंतर संद्रवण, कठोर कठिन मध्याह्न, प्रवर अपराह्न और परास्त संध्या, एक लम्बी रात, उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों जैसी दीर्घ रात, ये हैं कुछ एक विम्ब जीवित विम्बलोक के, लोक मानस के, लोक जीवन के"। ऋग्वेद में लोक समाज की एक विराट कामना की गई है। ऋग्वेद में स्थान दो के लिए "देहिता लोकम" का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा श्रीमद् भगवत् गीता में "लोक" तथा "लोक संग्रह" आदि शब्द आये हैं। बाद में तीन लोक, चौदह लोकों का उल्लेख मिलता है। भरत मुनि ने भी नाट्य शास्त्र में नाट्य धर्मी और लोक धर्मी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। महाभारत में लोक शब्द का प्रयोग साधारण जनता के लिए किया गया है। महर्षि व्यास जी अन्य स्थान पर लिखते हैं—

“प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नर”

अर्थात् "लोक को स्वयं देखने वाला व्यक्ति ही इसे सम्यक रूप में जान सकता है।" लोक शब्द को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। भारतीय लोक साहित्यकारों द्वारा अपनी अध्ययन प्रणाली में पाश्चात्य दृष्टिकोण का अनुसरण भी मिलता है। उन्होंने फोक शब्द के पारम्परिक अर्थ को ग्रहण किया। "फोक शब्द एंग्लो-सैक्शन के Folk शब्द से निष्पन्न हुआ है। जर्मनी में इसका उच्चारण volk किया जाता है"।

लोक संगीत – आदि मानव के समय से ही लोक में सामाजिक वातावरण की अनुभूति और निष्कपट अभिव्यक्ति से गुंफित, हम पुश्त दर पुश्त जो गीत गाते चले आते हैं वही नैसर्गिक पारम्परिक धुनों में जन सामान्य की सामूहिक रूप में संघर्ष, पीड़ा, खुशियों और कल्पनाओं में की गई मौखिक अभिव्यक्तियाँ लोकगीत कहलाती हैं। लोकगीत निसर्ग सम्पदा हैं, स्वयंभू हैं। लोकगीत सामान्य लोक जीवन से ही उपजते हैं। मानव मन में अनेक भाव होते हैं, प्रकृति और मन से मिलकर नैसर्गिक शब्दों द्वारा निस्तरित भाव काव्य कहलाते हैं। नैसर्गिक पारम्परिक धुनों में बद्ध काव्य और स्वच्छन्द गीत शैली को लोकगीत का नाम दिया जाता है। लोकगीतों की प्रवाहमयी धारा में लोक जीवन इटला-इटला कर बहता है और ये हर आने वाली पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं। ये परब्रह्म की भाँति अनन्त, अनादि और सर्वव्यापी होते हैं। लोकगीतों में हर समुदाय की अपनी अनुभूति व अपनी ही अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए गाँव के प्रांगण में हर व्यक्ति इनमें रल मिल जाता है। **लोकगीत हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर हैं। लोकगीत लोक संस्कृति के सच्चे संवाहक हैं।** लोक संगीत में पूरे समाज को संगठित करने की असीमित और अपार शक्ति है, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा से जुड़े हैं। लोक संगीत पूर्ण रूप से सदियों पुरानी मौखिक लोक परम्पराओं में अवगुंठित है। **जिनमें भाषा, भाव और संगीत द्वारा स्थान विशेष की लोक आभा झलकती है, प्रतिबिंबित होती है।** लोकगीतों में स्थान विशेष का इतिहास, भूगोल, सामाजिक परिवेश, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, कथा-व्यथा सब गीत शैली में गुंफित होते हैं। लोकगीत एक स्थान विशेष की पहचान करवाते हैं। लोकसंगीत लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र विशेष का अस्तित्व बचाने के लिए इनका लिखित, ध्वन्यात्मक और क्रियात्मक संरक्षण परम आवश्यक है।

लोक संगीत

लोक संगीत की पहुँच मानव की आत्मा तक है। असीमित रूप से यह पूरे विश्व को एक माला में पिरो सकता है। महान विभूतियों के कथनानुसार गढ़वाल के लोक संगीत को जाति या वर्ग के आधार पर वर्गीकृत नहीं

किया जा सकता, उनका विशेषज्ञ होना ही पर्याप्त है। लोक संगीत हमें अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में मिलता है, जिसकी रचना आम समाज द्वारा की गयी और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होकर पारम्परिक रूप में प्राप्त होती है। व्यक्ति विशेष की रचना सुगम संगीत के अंतर्गत आती है जिसके साथ रचनाकार का नाम हमेशा के लिए जुड़ा हुआ होता है। लोक संगीत आम समाज की धरोहर है जो व्यक्ति विशेष की न होकर आम समाज की, आम समाज के लिए होती है।

उत्तराखंड के लोक संगीत में भी गायन, वादन, नृत्य का समावेश है। **लोक संगीत भी "गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं "** संगीत की इस परिभाषा से विलग नहीं है। यहाँ के निवासियों को आदिकाल से ही संगीत अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है, जिसमें लोक मंगल की समृद्ध परम्परा है। गढ़वाल के अधिकतर लोकगीत संवाद प्रधान हैं। हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुशलता पूर्वक इनका सृजन किया एक पंक्ति एक समूह ने गाई तब तक दूसरे समूह ने अपनी कल्पना शक्ति से दूसरी पंक्ति का सृजन कर लोकार्पित कर दिया। धीरे-धीरे परंपरा वाचिक रूप में संवाहक बन गई। लोक संगीत के अन्तर्गत गायन, वादन और नृत्य शैली में अनेक लोकगीतों की परम्परा है जिन में जागर, माँगल, आँगन के गीत, थड्या, चौंफुला, झुमैलो, बाजूबन्द, खुदेड़, चौंछड़ी, खुदेड़, झोड़ा, छोपती, नाटी, छूड़ा, ताँदी, लामण, हारूल, झैंता, न्योली, छपेली, ऋतु प्रधान, तीज त्योहार प्रधान, मेला प्रधान, बालगीत, घस्यारी, हास्य-व्यंग्य लोकगीत, लोकगाथायें, घटना प्रधान, व्यवसाहिक लोकगीत प्रमुख है। सम्पूर्ण उत्तराखंड में गाये जाने वाले लोकगीत भाषा और संगीत की दृष्टि से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर परिवर्तनशील हैं, किन्तु अधिकतर में भाव एक ही हैं। लोक संस्कृति का यह भंडार संगीत द्वारा सामाजिक जीवन से संरक्षित आदर्श उद्देश्य, नीति, कल्पना, स्वप्न, प्रेम, आशा, कामना, इतिहास, भूगोल की एक समृद्ध, आत्मिक, हृदय ग्राही धरोहर है। इनमें कुछ लोकगीत नृत्य प्रधान, कुछ गायन व कुछ केवल भाव प्रधान हैं। यूँ तो भाव प्रधान सभी हैं किन्तु कुछ आलाप प्रधान भी हैं। कुछ लोकगीतों की संगत ढोल-दमौं, डौर-थाली, हुड़का, ढोलक, मोछंग से की जाती है। कुछ लोकगीत आलाप प्रधान या कुछ स्वतंत्र गायन रूप में प्रचलित हैं।

नारी सशक्तिकरण और सामाजिक संगठन में लोक संगीत की अहम भूमिका

लोक संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं का समावेश है। लोक संगीत का अविष्कार भी आम समाज में व्यक्ति विशेष ने नहीं सामूहिक रूप में किया गया है। लोकगीतों की मौखिक लोक परम्परा है जो समाज में अपने पूर्वजों से विरासत में मिलती है। लोक संगीत पर पूरे लोक का अधिकार होता है। जिसमें पूरे समाज को संगठित करने और सशक्त करने की अपूर्व शक्ति है। विशेषकर उत्तराखंड की नारी को जीवन की झंझावात झेलने के लिए दृढ़ता प्रदान करने में लोक संगीत की अहम भूमिका है। परिवार की धुरी वह नारी माँ, बेटा, बहू की भूमिका में पूरे परिवार के लिए समर्पित है।

पुरुष वर्ग अधिकतर सेना में या अन्यत्र रहते हैं। परिवार की पूरी जिम्मेदारी नारी शक्ति की ही होती है। वह अपने लिए न जी कर परिवार के लिए जीती है और सर्व समाज के सुख-दुःख में भागीदारी निभाती है। लोकगीत ही उनके सुख-दुःख को व्यक्त करने के उचित माध्यम होते हैं। लोकगीत गाकर मन हलका हो जाता है। जब संगठित होकर एक साथ मिलकर गायन, वादन और नृत्य द्वारा स्वयं और स्वजनों का मनोरंजन किया जाता है तो मनुष्य ही नहीं कोई भी प्राणी सुरलोक की अनुभूति में सब विषमताओं को भूल कर सकारात्मक रूप में

आत्मिक रूप से संगठित हो जाता है। जब आम गृहिणियों ने लोक संगीत का प्रशिक्षण लिया तो एक अंतराल के बाद निरंतर अभ्यास के उपरांत निर्भीकता पूर्वक मंच प्रदर्शन किया। लोक संगीत का मनमोहक प्रदर्शन करने पर समाज से प्रशंसित होने पर मन से सशक्त हुई। अपनी वेशभूषा को अपना कर अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित कर अपनी पहचान बनाने की प्रेरणाश्रोत बनीं। जब देश के अनेक स्थानों पर जाने का सौभाग्य मिला तो पुरस्कृत होने पर और सुअवसरों पर संस्कार लोकगीत मांगल गायन करने पर दक्षिणा प्राप्त करने पर धन से सशक्त हो रही हैं। जब लोकनृत्यों का अभ्यास करती हैं तो तन से सशक्त होती हैं। आज सैकड़ों बहिनें अपनी लोक संस्कृति के बल बूते पर आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं और सकारात्मक सोच अपनाकर आम समाज और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं।

कवि पुरुषोत्तम मिश्र 'गोनेर' जी की ये पंक्तियाँ हमेशा मेरे मन मस्तिष्क पर घूमती रहती हैं कि—

भूल गया जो संस्कार वो जीवन खरा नहीं रहता।

जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता।।

इसलिए मैं सबसे यही आग्रह करती हूँ कि अपनी लोक संस्कृति अपने मूल धरोहर को संरक्षित करना सबका परम कर्तव्य है। मूल है तो हम हैं वरना हमारी कोई पहचान नहीं है। लोक गीत एवं लोक संगीत लोक संस्कृति के सच्चे संवाहक हैं। लोक संगीत को संरक्षित और सवर्द्धित करना सबका दायित्व है। इस क्षेत्र में महिलायें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

किशोर स्वास्थ्य में निवेश क्यों करें ?

विमला मखलोवा,

State Project Coordinator

State Hub for Empowerment of Women

Women Empowerment and Child Development Department

Uttarakhand

सभी लोगों की तरह स्वास्थ्य विकास एवं जीवन के उच्चतम प्राप्त मानकों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने का मौलिक अधिकार किशोरों को भी प्राप्त है। यह वैश्विक मानवाधिकार उपकरणों द्वारा समर्थित हैं, जिन पर लगभग सभी देश एक मत हैं। यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक और जनआंकिकीय लाभ निश्चित रूप से होते हैं। किशोर स्वास्थ्य पर निवेश से तिगुना लाभ मिलता है। किशोरों हेतु कई राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाएं भी संचालित हैं जिनमें समस्त विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को एक मंच साझा करने की आवश्यकता है।

किशोरावस्था में स्वस्थ व्यवहार स्थापित करने हेतु सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है। योग एवं नियमित व्यायाम, खेलों में प्रतिभागिता, रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना इत्यादि इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखा गया है कि कई बार किशोर मादक द्रव्यों के सेवन, शराब और तंबाकू का उपयोग, मानसिक विकार, चोट और यौन संचारित संक्रमण इत्यादि से ग्रसित हो जाते हैं। उनकी समस्याओं का शीघ्र पता लगाने और उपचार करने हेतु सुदृढ़ व्यवस्था की अत्यंत आवश्यकता है। किशोरावस्था में स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने से वयस्क जीवन में रुग्णता, विकलांगता और समय से पूर्व मृत्यु दर को कम किया जा सकता है।

किशोरों में भावनात्मक कल्याण और प्रेरणादायी व्यवहारों को बढ़ावा देने की नितान्त आवश्यकता है। संघर्षों का प्रबंधन और समाधान इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। जोखिम कारकों जैसे पारस्परिक हिंसा, जल्दी गर्भधारण इत्यादि के सम्बन्ध में समुचित जानकारी भविष्य की संतानों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। किशोर स्वास्थ्य में निवेश सुरक्षित भविष्य का निर्माण करता है तथा बालपन में हुये स्वास्थ्य समस्याओं को भी किशोरावस्था में ठीक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में अपर्याप्त निवेश की स्थिति में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में पर्याप्त निवेश होने पर भी अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं।

निवेश व्यापक सामाजिक लाभ लाता है

किशोर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं आर्थिक एवं सामाजिक लाभ लाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, किशोर स्वास्थ्य में निवेश से मृत्यु दर और प्रजनन दर में गिरावट देखी गयी है, जो त्वरित आर्थिक विकास में योगदान करती हैं। प्रत्येक वर्ष कम जन्मों के साथ, एक देश की युवा आश्रित जनसंख्या कामकाजी आयु की जनसंख्या के संदर्भ में कम हो जाती है, जिससे तीव्र आर्थिक विकास के अवसर प्राप्त होते हैं।

किशोर स्वास्थ्य में निवेश संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक हैं। किशोरों का समुचित विकास, स्वास्थ्य या कल्याण सतत् विकास लक्ष्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ

है। किशोर स्वास्थ्य में निवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव विकास का एक अनूठा चरण है। इस निमित्त किशोर स्वास्थ्य के संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किशोर स्वास्थ्य को प्राथमिकता प्रदान करने की नितान्त आवश्यकता है।

किशोरों के स्वास्थ्य के लिए त्वरित कार्यवाही का आह्वान

विश्व स्तर पर, इस बात पर सहमति बढ़ रही है कि किशोरों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ अलग किया जाना चाहिए। 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच होने वाली तीव्र शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक वृद्धि और विकास; व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वैश्विक आबादी की बीमारी और चोट के बहुतायत मामले किशोरों से जुड़े होते हैं। इनमें से कई स्थितियां रोकी जा सकती हैं। इन विषयों पर अभी यथेष्ट प्रयास नहीं हुए हैं और उनमें अधिक ध्यान और निवेश करने की आवश्यकता है। किशोर विकास के महत्व को पहचानना एवं किशोर स्वास्थ्य और कल्याण को पूरी तरह से प्रोत्साहित और संरक्षित करने हेतु पर्याप्त निवेश करना ही सतत विकास की कुंजी है। वैश्विक समुदाय इस हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है।

सितंबर 2015 में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के समर्थन में महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य (2016–2030) के लिए ग्लोबल रणनीति शुरू की जो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है जिसमें प्रत्येक महिला, बच्चे और किशोर को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के अपने अधिकारों का एहसास हो, सामाजिक और आर्थिक अवसर हों, और वे समृद्ध और टिकाऊ समाज को आकार देने में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हों।

यह नई रणनीति किशोरों को 2030 एजेंडा के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक धुरी के रूप में पहचानती है, जिसमें समाज में व्याप्त गरीबी, भूख, शिक्षा, लैंगिक असमानता, स्वच्छता, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन इत्यादि शामिल हैं।

किशोर स्वास्थ्य हेतु मात्र नशा मुक्ति केन्द्र, परामर्श केन्द्र इत्यादि पर्याप्त नहीं हैं। किशोर स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है कि परिवार, शिक्षण संस्थाओं आदि के माध्यम के बाल्यकाल से ही किशोरों को उक्त संदर्भ में शिक्षित किया जाये। किशोर स्वास्थ्य में निवेश से भविष्य में वृद्धावस्था सम्बन्धी स्वास्थ्य मानकों में भी निश्चित रूप से सुधार होगा। साथ ही एक स्वस्थ नयी पीढ़ी की नींव मजबूत होगी। एक स्वस्थ किशोर देश के आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक सिद्ध होगा।

डा0 आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी पुस्तकालय : एक परिचय

आनन्द कुमार
पुस्तकालयाध्यक्ष (अ.प्रा.)
डा0 आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन
अकादमी, नैनीताल

पुस्तकालयों के माध्यम से मानव अपने दृष्टिकोणों, विचारों एवं अनुभवों तथा स्वप्नों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संप्रेषित करता है। भविष्य का निर्माण करने में पुस्तकालय सोपान भी है और अतीत की कड़ी भी, पुस्तकालय वर्तमान से भविष्य की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं। पुस्तकालय जैसी संस्था वर्तमान प्रजातंत्रीय युग की एक अभूतपूर्व देन है। किसी भी संस्था के सर्वांगीण विकास का आधार साक्षरता तथा शिक्षा का प्रसार है, किसी भी देश अथवा प्रदेश की सामाजिक, राजनैतिक, बौद्धिक और आर्थिक स्तर ऊँचा करने में पुस्तकालयों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। पुस्तकालय किसी भी संस्था की महत्वपूर्ण इकाई होती है। पुस्तकालय में न केवल प्रशिक्षण, शोध तथा विभिन्न विषयों से संबंधित प्रलेखों का संकलन किया जाता है, बल्कि पूरे संस्थान में होने वाली समस्त अकादमिक गतिविधियों का लेखा-जोखा भी प्रलेखन कार्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है।

अकादमी पुस्तकालय, अकादमी की साहित्यिक समृद्धि का द्योतक है। पुस्तकालय निरन्तर संकाय अधिकारियों/प्रशिक्षु अधिकारियों व अकादमी परिवार के लिए शैक्षणिक वातावरण तैयार करने तथा नित नवीन जानकारियों से अवगत कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अकादमी पुस्तकालय त्रिशूल भवन के भूतल पर लगभग 10000 वर्ग फीट के विशाल परिसर में स्थित है। पुस्तकालय को पाठकों की आवश्यकताओं के अनुसार सुरुचिपूर्ण रूप से विभिन्न कक्षाओं में व्यवस्थित किया गया है। कक्षाओं का व्यवस्थापन इस प्रकार किया गया है कि पाठकों को अपनी आवश्यकतानुसार अध्ययन सामग्री खोजने, प्राप्त करने तथा निर्गत करवाने में कोई कठिनाई न हो। अकादमी पुस्तकालय न केवल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अधिकारियों को सुविधा प्रदान करता है, बल्कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय में शोध कर रहे छात्रों को भी आवश्यक सूचना एवं परामर्श प्रदान करता है। अकादमी पुस्तकालय पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत है, आगम-निर्गम, संदर्भ सेवा, प्रलेखन सेवा इत्यादि में कम्प्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। अकादमी पुस्तकालय में संग्रहित पुस्तकों एवं अन्य प्रलेखों का सम्पूर्ण कैटलाग लिबसिस साफ्टवेयर में दर्ज है।

नवीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2020 में पुस्तकालय के लिए अकादमी द्वारा पुस्तकालय के पुराने साफ्टवेयर LIBSYS-4 के स्थान पर National Informatics Centre (NIC), Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India द्वारा विकसित Library automation software E-Granthalaya-4-0 on Cloud का क्रय कर लिया गया है। E-Granthalaya साफ्टवेयर में डाटा ईन्ट्री का कार्य गतिमान है।

Library Mission and Vision

“Academy Library seeks to select, acquire, preserve and disseminate the documents and information useful for trainee officers, faculty members, guest speakers and staff members for their capacity building”

अकादमी पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं तथा सेवाएं :-

सुविधाएं

- आनलाईन पब्लिक एक्सेस कैटलाग
- 50 से अधिक पाठकों के लिए अध्ययन कक्ष
- लेखों की फोटोकापी
- अकादमी संकाय व स्टाफ के अलावा विशेष सदस्यता
- सन्दर्भ सेवा
- सूचना खोज एवं परामर्श सेवा

सेवाएं

- पुस्तकों का आदान प्रदान
- मासिक नवीन पुस्तकों का पुस्तकालय में प्रदर्शन
- पुस्तकालय सन्दर्भ सेवा
- अधिकारियों को लेखों की फोटोकापी उपलब्ध कराना
- पुस्तकों को ढूढने में व्यक्तिगत सहायता
- आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के लिए उपयोगी सन्दर्भ पुस्तकों का पुस्तकालय में प्रदर्शन
- ऑनलाईन समाचार पत्र सेवा
- वाई-फाई सुविधा
- ऑनलाईन सर्च की सुविधा

संग्रह

- पुस्तकें एवं रिपोर्ट्स
- जिल्दबन्द पत्रिकाएं
- सी.डी.रोम्स
- मानचित्र
- विश्वबैंक प्रकाशन
- विश्वकोष
- सन्दर्भ ग्रंथ
- जनगणना पुस्तिकाएं
- इम्पीरियल गजेटियर
- हिमालयन गजेटियर

- सेटिलमेन्ट रिपोर्ट्स
- ए.आई.आर. मैनुअल्स
- विभागीय मैनुअल्स
- लॉ आफ अमेरिका
- हैल्सबरी लॉ आफ इंग्लैण्ड
- कलेक्टेड वर्क्स आफ महात्मा गाँधी
- सेलेक्टेड वर्क्स आफ जवाहर लाल नेहरू

अकादमी पुस्तकालय के सतत् विकास के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। पुस्तकों का चयन एवं क्रय, आनलाईन सेवाएं, पेपर क्लिपिंग्स, डिजिटल प्रलेखों की उपलब्धता इत्यादि के लिए भी प्रयास जारी है। निकट भविष्य में अकादमी की कुछ पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप में पाठकों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी प्रकार E-Granthalaya सॉफ्टवेयर में समस्त पुस्तकों की डाटा एन्ट्री पूर्ण हो जाने के बाद कोई भी पाठक अकादमी पुस्तकों को आनलाईन पब्लिक एक्सेस कैटलाग माध्यम से कहीं से भी देख सकता है।

अकादमी द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य में अकादमी पुस्तकालय को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत करके कम से कम Manpower से संचालित किया जा सके। वर्तमान समय के अनुसार यह आवश्यक भी है कि अकादमी पुस्तकालय को पूर्ण सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया जाये। अकादमी पुस्तकालय को Next Generation Library में उच्चिकृत करने के लिये आवश्यक है कि पुस्तकालय को Radio Frequency Identification Device (RFID) से सज्जित किया जाये। अकादमी पुस्तकालय के RFID System से सज्जित होने पर विभिन्न नैत्यक कार्यों में पुस्तकालय कर्मियों की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कम हो जायेगा।

उत्तराखण्ड में कृषि, पशुपालन एवं महिलाएँ

प्रो० बी०आर०पंत,
भूगोल विभाग,
एम० बी० रा० स्ना० महाविद्यालय, हल्द्वानी,
(उत्तरा पत्रिका से उद्धृत)

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से दो—रबी एवं खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। रबी के मौसम में गेहूँ एवं जौ, मटर, सरसों, लाही, मसूर तथा कुछ परम्परागत फसलें बोयी जाती हैं जबकि खरीफ में धान, मडुवा, झंगोरा, भट्ट, गहत, उड़द, राजमा, लोबिया के साथ—साथ परम्परागत दालें बोई जाती हैं। इन फसलों के बीच में आलू, गडैरी, प्याज तथा बेल एवं जड़ वाली सब्जियों को उत्पादन भी किया जाता है।

पर्वतीय क्षेत्र की खेती में आज भी महिलाओं का योगदान सर्वाधिक होता है। पर्वतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महिलाएं आगे हैं लेकिन सरकारी अभिलेखों में महिलाओं को गृहिणी अधिक, अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में कम पंजीकृत किया गया है जो वस्तुस्थिति को प्रदर्शित नहीं करता है। उत्तराखण्ड के कई हिस्सों में आज भी महिलाओं द्वारा पुरुषों के लिये तथाकथित रूप से आरक्षित कार्य जैसे हल जोतना, घास के लुटे (ढेर) लगाना, दीवारें बनाना, लकड़ी चीरना, पेड़ों से चारा काटना आदि भी सम्पादित किये जा रहे हैं। कुमाऊँ में किये गये एक अध्ययन के अनुसार जिसमें 135 विभिन्न श्रेणी—सामान्य, धात्री एवं गर्भवती महिलाओं को सम्मिलित किया गया है, कुल सर्वेक्षित (135) महिलाओं में से 2.21% महिलाएं चौबीस घण्टों में आठ घण्टे से कम कार्य करती हैं, बारह घण्टे कार्य करने वाली 20.59% महिलाएं थीं, जबकि सर्वाधिक 59.56% महिलाएं प्रतिदिन 18 घण्टे कार्य करती थीं। कुल 135 महिलाओं में से 17.64% महिलाएं ऐसी भी थीं जो प्रतिदिन 16 से 20 घण्टे कार्य करती थीं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कमाबेश उत्तराखण्ड की लगभग 77% (तीन चौथाई) महिलाएं 16 या इससे अधिक घण्टे कार्य करती हैं क्योंकि प्रातः उठने से लेकर देर रात तक घर एवं बाहर के सभी कार्यों का निष्पादन उनको करना होता है। यह दिनचर्या खेती के मुख्य कार्यों के अतिरिक्त दिनों में कुछ कम हो सकती है लेकिन इस अन्तराल में भी महिलाओं को घास, लकड़ी, ईंधन इकट्ठा करने जैसे कार्यों के अतिरिक्त अन्य मरम्मत के कार्य करने होते हैं। कुछ महिलाओं को घर एवं गौशाला बनाने के लिए सामग्री इमारती लकड़ी, पत्थर, मिट्टी आदि इकट्ठा करने जैसे कार्य करने पड़ते हैं। यहाँ पर इसका उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रतिदिन इतना कार्य करने के बावजूद महिलाओं द्वारा अपने भोजन एवं पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फलस्वरूप महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही हैं और उनमें औसत रूप से प्रोटीन विटामिन ए1, बी2, सी आदि की कमी पाई गई। इन आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से महिलाओं का शरीर सूचकांक भी मानकों के अनुसार नहीं पाया गया। कुपोषित होने के कारण ये अनेक बीमारियों से ग्रसित थीं तथा नवजात शिशु भी कुपोषित होने के साथ इनका वजन भी सामान्य से कम पाया गया (पन्त, 2004)।

खेती के साथ पशुपालन भी पर्वतीय समाज का अभिन्न हिस्सा है। इन्हें अलगकर नहीं देखा जा सकता है। कुछ लोग खेती की भूमि न होने के बावजूद शहरों के बीच में भी पशुपालन करते हैं। शहरों में चारा आदि क्रय कर आपूर्ति की जाती है जबकि गाँवों में महिलाओं को सभी कार्य स्वयं ही करने पड़ते हैं।

उत्तराखण्ड में 13 जनपद हैं। जिनमें से केवल 8.7% भूमि तराई एवं भाबर में स्थित हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर जनपदों में है जबकि शेष 91.3% भूमि 11 जनपदों में है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल एवं चम्पावत के मैदानी भागों को भी जोड़ दिया जाय तो लगभग 15% भूमि ही मैदानी है शेष 85% भू-भाग नदी-घाटियों, मन्द एवं तीव्र ढाल, शिखरों के साथ बर्फीले क्षेत्र हैं। उत्तराखण्ड के भूमि-उपयोग का मात्रात्मक अध्ययन करने के लिये वर्ष 2019-20 की सांख्यिकीय डायरी में संकलित सूचनाओं का प्रयोग करना उचित होगा। वर्ष 2018-19 में कुल प्रतिवेदित भूमि (60019.24 हेक्टेयर) में से लगभग 64% भूमि वनों के अन्तर्गत है। यहाँ पर स्पष्ट करना उचित होगा कि उत्तराखण्ड का कुल क्षेत्रफल अलग-अलग विभागों द्वारा अलग-2 दिया गया है, प्रतिवेदित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल से अधिक होता है। उत्तराखण्ड का 64% क्षेत्र जंगलों के अन्तर्गत प्रदर्शित किया गया है। यह वह भूमि है जो वन विभाग के अन्तर्गत है। लगभग 21 से भी कम भूमि वनाच्छादित है। कुल क्षेत्र में से 4% भूमि पर खेती नहीं की जा सकती है। खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि के अन्तर्गत केवल 3% भूमि है। वर्ष 2018-19 तक भी समग्र रूप से 5% कृषि योग्य क्षेत्र बेकार है, जिसे मानव उपयोग में लाया जाना शेष है। सामान्य रूप से देखा जाय तो प्रत्येक गाँव में पशुओं के चरने के लिए गौचर भूमि होती है जिसे सरकारी भूमि वर्ग चार में सम्मिलित किया जाता है लेकिन आँकड़ों के अनुसार मात्र 3% भूमि क्षेत्र ही स्थाई चरागाहों के अन्तर्गत सम्मिलित है। यह भूमि अधिकांश रूप में पर्वतीय जनपदों के उच्च स्थानों में ही पाई जाती है। सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में वृक्षों, झाड़ियों तथा बगीचों के अन्तर्गत भी 7% भूमि क्षेत्र पंजीकृत है। पुरानी एवं नवीन परती के अन्तर्गत लगभग 14% भूमि की गणना की गई है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना उचित है कि इस परती भूमि पर कभी खेती की जाती थी लेकिन उत्पादन कम एवं श्रम अधिक होने के कारण लोगों ने इस भूमि पर खेती करना बन्द कर दिया है। अब जब पर्वतीय भागों से आबादी का पलायन हो रहा है, उनकी छोड़ी गई भूमि भी परती भूमि के रूप में परिवर्तित हो रही है। यह भूमि भी अपने उपयोग हेतु नई तकनीक, नई सोच एवं नये कार्य करने वाली पीढ़ी की प्रतीक्षा कर रही है। उत्तराखण्ड में लगभग 20% भूमि ऐसी है जिसका मानव हित में उपयोग किया जाय तो आबादी के एक बड़े हिस्से का पलायन होने से रोकने के साथ-2 आजीविका के नये-2 उद्यमों की सहायता से राज्य की आय बढ़ाई जा सकती है जिससे समाज के अतिरिक्त प्रदेश सरकार भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि समग्र रूप में उत्तराखण्ड की मात्र 11% भूमि पर ही खेती की जाती है। उत्तराखण्ड के अधिकांश जिले ढालदार पर्वतीय हैं— उत्तरकाशी (3.61%), चमोली (3.7%), रूद्रप्रयाग (8.2%), टिहरी (10.4%), पौड़ी (6.7%), देहरादून (9.7%), पिथौरागढ़ (5%), अल्मोड़ा (14.7%), नैनीताल (10.2%), बागेश्वर (10.8) एवं चम्पावत (6.8%) में औसत 7.2% भूमि पर ही खेती की जाती है। जबकि सिंचाई उपलब्ध मैदानी जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में क्रमशः 46.8% एवं 49.1% भूमि पर ही उन्नत खेती की जाती है। पर्वतीय जिलों में 1 से कम भूमि पर खेती होती है। मैदानी जनपदों के कारण भी कई बार उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों की वास्तविक स्थिति का आंकलन नहीं हो पाता क्योंकि वह औसत को हमेशा बढ़ा देता है। शुद्ध बोए गये क्षेत्रफल में मात्र 58.85 भूमि ही ऐसी है जिस पर एक से अधिक बार खेती की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई आदि की सुविधाएं एवं अनुकूल जलवायु की अनुपलब्धता के कारण साल में लगभग 41.15% भाग में एक ही फसल बोई जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भूमि को बहुत कम समय खाली अथवा उर्वरकता बनाये रखने को मिलता है। सिंचाई के संदर्भ में भी उत्तराखण्ड का औसत सिंचाई क्षेत्रफल लगभग 50% है। जबकि पर्वतीय कृषि भूमि जो नदी

घाटियों में है, केवल 2% से कम क्षेत्र को ही सिंचाई की सुविधाएं मिल पाती हैं, जबकि मैदानी खेती की भूमि के 98% भाग को ट्यूबवैल एवं नहरों द्वारा सिंचाई मिल जाती है।

पर्वतीय क्षेत्रों की खेती का लगभग सम्पूर्ण कार्य महिलाओं द्वारा ही सम्पन्न किया जाता रहा है क्योंकि पहले से ही पुरुषों का रोजगार के लिए पलायन होता रहा है। जब तक बच्चे रोजगार में नहीं लग जाते हैं, 18-20 वर्ष के होते हैं, तब तक अपने परिवार के साथ खेती एवं पशुपालन में मदद करते हैं जबकि कुछ नवयुवक अपने पिता/सगे संबंधियों के साथ अध्ययन के लिए बाहर चले जाते हैं। महिलाओं को गाँवों में बच्चों एवं बुढ़ों की देखभाल भी करनी पड़ती है। यह बड़ी आबादी का अनुत्पादक एवं पूर्ण रूप से निर्भर रहने वाली होती है।

महिला जनसंख्या में कार्यशील महिलाएं –

अद्यतन (2021) जनगणना न होने से वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तराखण्ड की कुल आबादी में से मात्र 38.4% आबादी ही कार्यशील अथवा खेती या अन्य व्यावसाय से जुड़ी थी। पुरुषों की आबादी में से 49.7 प्रतिशत कार्यशील श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, लेकिन आधी आबादी वाली महिलाओं में से एक चौथाई से थोड़ा अधिक मात्र 26.7% महिलायें ही कार्यशील की श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित थीं। पूर्ण रूप से पर्वतीय जनपदों में औसत 40% से अधिक महिलाएं कार्यशील थीं जबकि मैदान में स्थित जनपदों में महिलाओं की भागीदारी 20% से भी कम हो गयी है। इस असन्तुलन का कारण स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में खेती मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है और मैदानी क्षेत्रों में खेती मशीनों के द्वारा की जाती है जहाँ महिलाओं की भागीदारी कम हो जाती है। सबसे अधिक बागेश्वर (47.9%), रुद्रप्रयाग (47.5%) एवं अल्मोड़ा (47.0%) जनपद की महिलाएं कार्यशील श्रेणी में हैं जबकि सबसे कम हरिद्वार (9.1%), देहरादून (15.4%) एवं उधमसिंहनगर (18.6%) में कार्य करने वालों की श्रेणी में थीं। कार्यशील श्रेणी को मुख्य कर्मकर एवं सीमान्त कर्मकर की श्रेणी में विभाजित कर देखते हैं तो महिला कार्यशील आबादी में से मात्र 60.6% महिलाएं मुख्य कर्मकर थी, शेष सीमान्त कर्मकर थीं, जिन्हें वर्ष में 100 दिनों से कम कार्य मिलता है, जबकि पुरुष कार्यशील आबादी में से 81.1 % पुरुष मुख्य कर्मकर हैं। अकार्यशील आबादी को देखें तो 50.3% पुरुष एवं 73.3% महिलाओं के पास कोई भी कार्य /व्यवसाय नहीं है। यह विरोधाभास है कि पहाड़ की 73.3% महिला आबादी अकार्यशील है, जहाँ लड़कियों को बचपन से ही घर के कार्यों के अतिरिक्त लकड़ी इकट्ठा करना, जानवरों को चुगाना, जानवरों के लिए चारा, घास लाना जैसे कार्य अनावरत करवाये जाते हैं।

मुख्य कार्यशील महिला जनसंख्या में महिला कृषक

जनगणना विभाग द्वारा मुख्य कार्यशील आबादी को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तराखण्ड में कुल कर्मकर आबादी में से 36.4% व्यक्ति ही कृषक की श्रेणी में है जिसमें से पुरुषों में 26.3% एवं महिलाओं में से 62.5% कृषक के रूप में पंजीकृत है। सबसे अधिक 89.2% महिलाएं रुद्रप्रयाग जनपद में हैं जबकि उत्तरकाशी (86.1%), चमोली (83.8%), पिथौरागढ़ (82.1%) एवं टिहरी की 81.9% महिलाओं की कृषक के रूप में गणना की गयी है। सबसे कम कृषक महिलाएं 11.3% हरिद्वार, 19.31% उधमसिंहनगर एवं 21.7% देहरादून जनपदों में हैं। पर्वतीय क्षेत्र की खेती में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। जबकि मैदानी क्षेत्र चाहे वह हरिद्वार व उधमसिंह नगर हो या देहरादून एवं नैनीताल, पौड़ी, टिहरी जनपदों के मैदानी क्षेत्र हों, यहाँ महिलाओं की भागीदारी कम होती है

क्योंकि खेती में मशीनों का प्रयोग होता है जो सामान्यतः पुरुषों द्वारा संचालित होती हैं। यह भी देखा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पुरुषों की आबादी पलायन के कारण कम हो रही है। अतः कृषि से सम्बन्धित सभी कार्य महिलाओं द्वारा ही संचालित होते हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में पुरुषों का मैदान में पलायन होने से महिलाओं की आबादी कम होती है। अनेक बार देखा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों की जुताई जैसा कठिन कार्य भी महिलाओं के द्वारा सम्पादित किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किये जाने वाले कठिन कार्यों के लिये अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ती है।

मुख्य कार्यशील महिला जनसंख्या में महिला कृषि मजदूर

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड की आबादी में कुल मुख्य कर्मकरों में से केवल 8.6% लोग ही कृषि मजदूर की श्रेणी के अन्तर्गत हैं। कम कृषि मजदूर होने का कारण यहाँ का सीमित कृषि क्षेत्र है। छोटे-2 सीढ़ीदार खेतों, ढालू भूमि, सिंचाई के लिए पानी की कमी आदि के कारण छोटे पैमाने पर ही खेती की जाती है जिसे वहाँ के लोग स्वयं कर लेते हैं या कभी जरूरत पड़ने पर अपने ही गाँव के लोगों की मदद से पूरा लक लेते हैं। कृषि मजदूरों में से 9.5% पुरुष हैं। सर्वाधिक पुरुष कृषि मजदूर उधमसिंह नगर (22.5%) एवं हरिद्वार (15.5%) जनपदों में पंजीकृत हैं क्योंकि तराई-भाबर क्षेत्र में खेती के लिये मशीनों का प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों की सहायता हेतु मैदानी क्षेत्रों के उक्त जनपदों में 30.4% एवं 13.7% कर्मकर महिलाएं भी कृषि मजदूर के रूप में कार्य करती हैं। उत्तराखण्ड में केवल 6.4% महिलाएँ ही कृषि मजदूरी से अपना भरण पोषण करती हैं। नैनीताल एवं देहरादून जनपदों में क्रमशः 8% एवं 4% महिला मजदूर पायी जाती हैं। इन जनपदों का कुछ क्षेत्र मैदानी है जिस पर खेती करने के लिए महिला मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश कृषि मजदूर अनुसूचित जाति के भूमिहीन लोग होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना तक भी उत्तराखण्ड का जनसंख्या परिदृश्य बहुत बदल चुका था, जिसमें कृषि मजदूरों का पाया जाना तो बहुत कम है लेकिन अन्य मजदूरों की संख्या में विगत दशकों से वृद्धि देखी गयी है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं की कृषि में भूमिका

उत्तराखण्ड में कुल महिलाओं की अपेक्षा अनुसूचित जाति की महिलाएं अधिक अनुपात में कार्यशील होती हैं क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों में खेती के अलावा अन्य व्यवसायों में प्रतिनिधित्व बहुत कम होता है। इनकी कुल महिला आबादी में से वर्ष 2011 में 28.6% महिलायें कार्यशील की श्रेणी में हैं जिनमें से 58.2% मुख्य कर्मकर तथा शेष सीमान्त कर्मकर की श्रेणी में है। कार्यशील आबादी अधिक होने के कारण अनुसूचित जाति की 63.3% महिलायें कृषक की श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। सर्वाधिक 91.7% कृषक महिलायें उत्तरकाशी जनपद में, जबकि सबसे कम 5.6% के साथ हरिद्वार जनपद की शिल्पकार महिलायें कृषक हैं। रुद्रप्रयाग जनपद 89.6% के साथ दूसरे स्थान पर है। समस्त पर्वतीय जनपदों की शिल्पकार महिलायें कार्यशील आबादी में से 15% से कम महिलायें खेती से जुड़ी हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में शिल्पकार जाति के लोगों द्वारा खेती के अलावा अन्य व्यवसाय नहीं होते हैं। अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में फौले जनपदों यथा देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में शिल्पकार जाति के लोगों के पास खेती की भूमि कम होने के कारण संलग्नता कम ही है।

कृषि के साथ ही उत्तराखण्ड की 10.3% शिल्पकार महिलाएं कृषि मजदूरी करती हैं, जिन लोगों के पास भूमि नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है या परिवार बड़े होते हैं, वे कृषि मजदूर के रूप में कार्य करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में 5% से कम शिल्पकार महिलायें खेती में मजदूरी का कार्य करती हैं जबकि मैदानी जनपद उधमसिंह नगर में सर्वाधिक 44.8% महिलायें वर्ष 2011 के अनुसार कृषक मजदूरी करती थीं। दूसरे स्थान पर हरिद्वार है, जहाँ 26.41% शिल्पकार महिलायें कृषि मजदूर के रूप में पंजीकृत थीं। नैनीताल एवं देहरादून जनपदों में भी क्रमशः 12% एवं 6.8% अनुसूचित जाति की महिलाएं कृषि मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाती थीं।

विश्लेषण से स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि की कमी होने के कारण बहुत कम महिलायें कृषि मजदूरी करती हैं क्योंकि यहाँ खेती के अधिकांश कार्य आपस में मिलजुल कर सम्पादित किये जाते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कृषि भूमि की अधिकता एवं कार्य करने वाली आबादी की कमी के कारण अनुसूचित जाति की महिलाओं द्वारा मजदूरी के कार्य सम्पादित किये जाते रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में शिल्पकार लोगों को साल भर कार्य करने के बदले में फसल कटने के बाद वर्ष में दो बार मजदूरी के रूप में (डडवार के रूप) अनाज दिया जाता था।

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की कृषि में भूमिका

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल मुख्य कर्मकरों में से उत्तराखण्ड की 57.7% जनजातीय लोगों की कृषक के रूप में गणना की गई जिसमें से 56.5% पुरुष एवं 60.4% जनजातीय महिलायें कर्मकरों की श्रेणी में थे। जहाँ तक महिला कृषक का प्रश्न है, सर्वाधिक 75.8% जनजातीय महिला कृषक देहरादून जनपद में हैं क्योंकि जौनसारी जनजाति के लोग कृषि पर ही अधिक निर्भर हैं। यहाँ पुरुषों से अधिक महिलाएं कृषक हैं। उत्तराखण्ड के जिन जनपदों में जनजातीय आबादी कम है, वहाँ महिला कृषकों का अनुपात भी कम है। जबकि उधमसिंहन नगर में थारू एवं बोक्सा की आबादी अधिक होने के बाद भी अनुपात कम है क्योंकि यहाँ भी जनजातियों ने पैसे उधार लेकर अपनी जमीनें रेहन/किराये/गिरवी में रख दी हैं जिससे इनके पास जमीनें नहीं हैं और ये कृषि मजदूर के रूप में अपनी ही जमीन पर कार्य कर रहे हैं।

जनजाति के लोग खेती के अलावा खेत-मजदूरी भी करते हैं। उत्तराखण्ड की जनजातीय आबादी के कुल कर्मकरों में से 14% व्यक्ति कृषि मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं। इनमें 14.6% महिला तथा 13.7% पुरुष कर्मकरों में से कृषि मजदूर हैं। महिला कृषि मजदूर सर्वाधिक 54.2% चम्पावत जनपद की जनजातीय महिलाएं हैं क्योंकि चम्पावत में राजि/वनरावत जनजाति के लोगों के पास खेती की भूमि नहीं है, इसलिए कृषि कार्यों में मजदूरी कर जीवन निर्वाह करती हैं। यद्यपि हरिद्वार में जनजातीय आबादी बहुत कम है लेकिन उनमें से भी 32.5% महिला कृषि मजदूर हैं। नैनीताल एवं पौड़ी के भाबर क्षेत्र में बुक्सा जनजाति की आबादी रहती है। जनगणना 2011 में कुल महिला कर्मकरों में से 17.8% एवं 13.4% महिलाएं कृषि मजदूरी करती हैं। यहाँ पर स्पष्ट करना उचित होगा कि पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर एवं उत्तरकाशी में जनजातीय महिलाएं कृषि मजदूरी नहीं करती हैं, वे अपनी आजीविका चलाने के लिए घरेलू उद्यमों में कार्य कर जीवन निर्वाह करती हैं।

पशुपालन में महिलाओं की भूमिका

20वीं पशुधन गणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड में लगभग 27.18 लाख गाय तथा भैंसे पाली जाती हैं। भेड़ एवं बकरियों की आबादी भी 16.56 लाख है। शेष पशुओं में खच्चर, गधा, टट्टू, सूअर, कुत्ते, खरगोश एवं

कुक्कुट पालन किया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख करना उचित होगा कि पशु-पालन में भी उत्तराखण्ड की महिलाओं का अहम योगदान होता है। चारे की व्यवस्था से लेकर गौशाला की सफाई, चरागाहों में जानवरों के छोड़कर, वापस लाना, दैनिक एवं वर्ष भर के लिए घास की व्यवस्था कर सुरक्षित रखना आदि सभी कार्य महिलाओं के द्वारा ही सम्पादित किये जाते हैं। दूध की बिक्री का कार्य भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। कहीं-2 पुरुषों द्वारा भी सहयोग किया जाता है। पशुओं के व्यापार में पुरुषों का हाथ होता है। चारे की व्यवस्था में महिलाओं को जंगली जानवरों से लेकर पेड़ों/पहाड़ों से गिरने की दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्तराखण्ड की कृषि एवं पशुपालन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका रहती है। निःसन्देह भौगोलिक दुरुहता, मौसमी प्रतिकूलता एवं तकनीकी ज्ञान की अनुपलब्धता के बाद भी खेती एवं पशुपालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी सक्रियता के बिना पहाड़ की अर्थव्यवस्था का संचालन सम्भव नहीं है। जरूरत इस बात की है कि खेती में नए तरीकों को ईजाद कर महिलाओं के शारीरिक श्रम को कम कर उसके जीवन में खुशहाली लाई जाय। इसी प्रकार पशुपालन के क्षेत्र में भी पर्वतीय भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु की दशाओं के अनुसार नई उन्नत नस्लों एवं तदनुरूप चारा विकास कर उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। इस दिशा में महिलाओं के अतिरिक्त नवयुवकों को आकर्षित कर योजनाबद्ध ढंग से पलायन को भी सीमित किया जा सकता है। उत्तराखण्ड की भूमि संवर्धन हेतु कृषि एवं पशुपालन का विकास किया जाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य अभी शेष हैं।

प्रयासों की कहानी
जनपदों की जुबानी

Minor Irrigation Division, Nainital

Summary

Name of Best Practice: Installation of Solar Lift Irrigation Scheme, Village Lugar, Block Okhalkanda, District Nainital

District: Nainita

Department- Minor Irrigation Division, Nainital

Contact Detail of Nodal Officer- Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Nainital

Brief Description:

The Scheme is running in Village Lugar, Gram Panchayat Badon of Aspirational Block Okhalkanda, District- Nainital. The intervention has immensely lifted the confidence of the fifteen Farmers and they have been able to take advantage of it for livelihood and for income generation purpose.

Benefits:

The scheme is very beneficial as one scheme covers four-hectare agriculture land for irrigation purpose, electricity production of about rupees twenty-two lacs sixty thousand during its service life as well as saving of fuel consumption of about Rupees thirty-five lacs. It has resulted in reverse migration in hilly areas of the state.

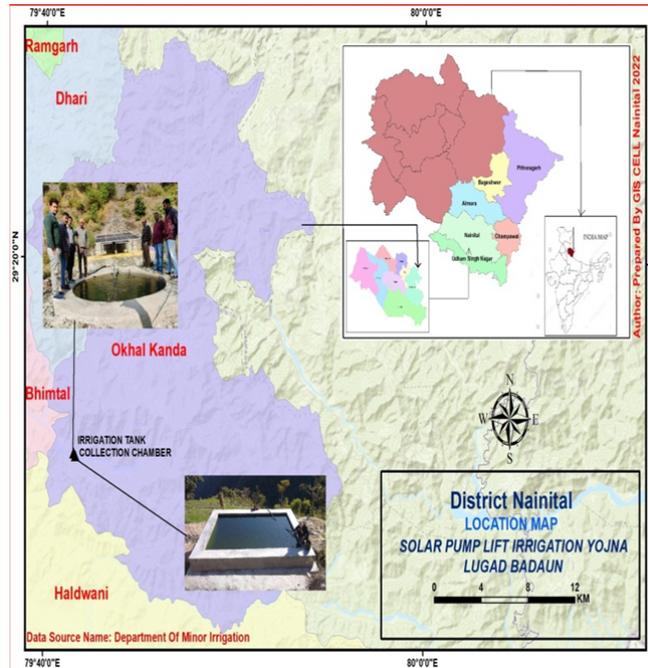
Challenges:

This scheme has been prepared for the accumulated area of agriculture in village Lugad of village Panchayat Badon. It is in a hilly place where it was not possible to irrigate land by flat irrigation due to the fact that the field is at a vertical distance of one hundred twenty-five metre from the river. Now at present four-hectare area is being irrigated by this lift scheme. Low income of farmer and migration was other challenge in the region.

Suggestions:

In nutshell Solar Lift Irrigation Scheme is now in initial stage and needs more collaboration with stakeholders for turning it into a model Scheme. Such a scheme should be established in other places also, so that the farmers can be benefitted by irrigating the non-irrigated area. It results in higher income which eventually facilitates reverse migration.

Location Map of Scheme – Solar Lift Irrigation Scheme Lugad (Badon)



Description of the Best Practices-

1-Does the solution/intervention entail the establishment of an institutional framework (Policy or Legal framework/SOP for monitoring)

Though no legal framework is in place, however, the intervention has immensely uplifted the confidence of the 15 Farmers and they are able to take it up for livelihoods and for income generation. The user group has already created for monitoring.

2- Does the solution/intervention involve a change in/establishment of certain governance mechanisms (e.g., constitution of steering committees, inter-agency collaboration, decentralization)?

The governance mechanism is already established in the village and the user groups have been already created and trained for operation so no additional establishment in governance mechanism is required.

3- Does the solution/intervention entail steps for promoting inclusiveness (e.g., mechanisms for citizen engagement in monitoring)?

It has been initiated to bring the local villagers under the umbrella by creating awareness and concept of solar based pumping system.

4- Are any capacity building/training initiatives undertaken for monitoring purposes as part of the solution/intervention?

Skill building and operational training has been given to user groups of concerned villages by the Department.

5- Are any steps taken to ensure transparency as part of the solution/intervention (e.g., progress on various programme /scheme Indicators captured by a monitoring dashboard is shared with the public on a real-time basis)?

User groups were created through open meeting in Gram panchayat to ensure transparency.

6- Are any steps taken to ensure that the solution/intervention is sustainable?

The sustainability of Solar panel is 25 years and submersible pump is 05 years respectively under warranty given by manufactures. Guidelines regarding solar lift irrigation scheme is available on www.mnre.gov.in.

7- How is the credibility of the solution/intervention ensured (e.g., specific process for ensuring data quality, mechanism for indicator review)?

As per guidelines of MNRE it should be implemented as long durability, pollution free, maintenance free mechanism and manufacturers have given 25 years warranty for the same.

Name of Scheme - Solar Lift Irrigation Scheme Lugad (Badon)

Total Area to be Irrigated=4-00 Hectare

CCA at Presen =4-00 Hectare

- Irrigated Area in Rabi before the Construction & Installation of this scheme= 0.50 Hectare
- Irrigated Area in Kharif before the Construction & Installation this scheme= 0.80 Hectare
- Irrigated Area in Jayad before the Construction & Installation of this scheme= 0.00 Hectare

Value of Production before Construction & Installation Scheme

S. N.	Fasal	Name of Crop	Area	Produce				By-Product				Net Produce	Cost of Production		Net Cost of Produce
				@	Total	Rate	Value	@	Total	Rate	Value		@	Value	
				Ha	Q/Ha	Q	Rs/Q	Rs.	Q/Ha	Q	Rs/Q		Rs.	Rs.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Rabi/ Un-Irrigated	Wheat	0.50	18	9	1000	9000	35	17.5	200	3500	12500	9350	4675	7825
2	Kharif/ Un-Irrigated	Paddy	0.80	13.33	10.66	1200	12796.8	26.5	21.2	200	4240	17036.8	7000	5600	11436.8
3	Jayad/ Irrigated	Potato	0.00	47.5	0	1200	0	47	0	200	0	0	14900	0	0
							21796.8					29536.80			19261.8

Value of Production after Construction and Installation Scheme

S. N.	Fasal	Name of Crop	Area	Produce				By-Product				Net Produce	Cost of Production		Net Cost of Produce	
				@	Total	Rate	Value	@	Total	Rate	Value		@	Value		
				Ha	Q/ Ha	Q	Rs/ Q	Rs.	Q/ Ha	Q	Rs/Q		Rs.	Rs. / Ha		Rs.
1	Rabi/ Irrigated	Wheat	2.80	35	98	1000	98000	36	100.8	200	20160	118160	18700	52360	65800	
2	Kharif/ Irrigated	Paddy	3.20	47.5	152	1200	182400	47	150.4	200	30080	212480	14900	47680	164800	
3	Jayad/ Irrigated	Potato	1.20	47.5	57	1200	68400	47	56.4	200	11280	79680	14900	17880	61800	
							348800					61520	410320			292400

An Amount of Rupees 2.73 Lac increased in income of Farmers after Installation and Construction of Scheme

Name of Scheme - Solar Lift Irrigation Scheme Lugad (Badon)

S.N.	Name of Scheme	GP	Head	Year	Construction Cost (Lac)			Latitude/ Longitude	Solar Pump Power (HP)
					D.P	MANREGA	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Solar Pump Lift irrigation Scheme Lugad	Badon	District Plan	2021-22	5.43	4.42	9.85	N29°13'40.1" E79°41'39.7"	5

Make In Pump (Manublock/ Submersible)	Type of scheme	Solar Pump No's	Adjective water uncountable	Water in Source (LPM)	Solar Pump Discharge in Houz (LPM)	CCA
11	12	13	14	15	16	17
Submersible	Surface Water	1	0	400	76.19	4.00

8- Does implementing the solution/intervention necessitate a specific financing mechanism to be put in place?

Without finance the intervention sustainability cannot be assured. Thus, already the support of schemes is taken up by District Plan/State plan under state government and PMKSY Scheme under central government. Still, it is beginning and long journey has to be followed.

How is technology leveraged?

The guideline regarding solar lift irrigation scheme is available on www.mnre.gov.in.

Impact of implementing the practice

The scheme is very beneficial as one scheme covers 04-hectare land for irrigation purpose, electric production of about rupees 22.60 lacs during its service life as well as saving of fuel consumption of about Rupees 35 lacs. After installation in villages, it will uplift standard of living by adding extra income through agriculture production at low cost. It will also contribute in additional energy production and will be shared with power grid.

How the best practices can scale up/replicated?

The cluster approach can be implemented in the nearby villages/other part of district so that same result can be garnered which will ultimately benefit the people of the intervened area.

मनरेगा तालाब से स्रोतों का पुनरुद्धार एवं भूमिगत जल में वृद्धि

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
रुद्रप्रयाग के सौजन्य से प्राप्त

तालाब निर्माण कुरछोला-2021-22

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत फोकस कार्य के लिए चयनित बैडलैण्ड एरिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुरछोला की बच्चवाड नामी तोक समुद्रतल से 2080 मी0 की ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक रूप से पूर्ण स्थल है।



यहां पर सेब, आड़ू, अखरोट, नाशपाती एवं विभिन्न प्रकार के मौसामी फलों एवं सब्जियों का उत्पादन ग्राम पंचायत कुरछोला के 60 परिवारों द्वारा किया जाता है। बांज एवं विभिन्न प्रकार की प्रजाति के पेड़ों से घिरे इस क्षेत्र में पानी के महात्मा गांधी नरेगा के तहत तालाब का निर्माण किया जा रहा है। उक्त तालाब के आस पास महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत कई चाल खाल भी बनाई गई है। प्रारम्भ में इस क्षेत्र में दलदली मिट्टी के पोखर बने हुये थे जिन पर केवल मानसून के समय ही पानी की ठहरता था, एवं ग्रीष्म काल में ग्राम पंचायत के सारे स्रोतों में पीने के पानी की कमी हो जाती थी। पोखर तालाब निर्माण के पश्चात् पुनः स्रोतों में पानी के लेबल में वृद्धि देखी गई है।

योजना से लाभ—

- पहले ग्राम पंचायत कुरछोला के पानी के स्रोतों में पानी का स्तर 20 सेकेण्ड प्रति 1ली0 था। जल सम्बर्धन कार्यों के बाद स्रोत के पानी में 5 सेकेण्ड प्रति 1 ली0 का सुधार हुआ है।
- ग्राम पंचायत कुरछोला, धारकोट, पांजणा एवं नाग के 6 स्रोतों में पानी की कमी दूर हुई।
- आजिविका के तहत बागवानी का विकास सेब, अखरोट, आड़ू की पैदावार में वृद्धि।
- महात्मा गांधी नरेगा के तहत बने तालाबों से प्रवासीय को रोजगार एवं बागवानी से कास्तकरों को आय में वृद्धि।
- ग्राम पंचायत कुरछोला में कोविड के दौरान बाहर से आये हुये 35 युवाओं द्वारा इस क्षेत्र में बागवानी, घेरवाड एवं तालाब निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
- बागवानी एवं सब्जी उत्पादन से प्रत्येक व्यक्ति 30 हजार रुपये तक का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ इस कोविड-काल में लाभार्थी द्वारा बताया गया है।
- बागवानी में हुये उत्पादों को लाभार्थियों द्वारा लोकल मार्केट के अतिरिक्त बाहरी क्षेत्रों में भी भेजा जा रहा है जिससे इस क्षेत्र में प्रति कास्तकार वार्षिक 50 हजार रुपये इस क्षेत्र से प्राप्त कर रहा है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना बिन्दु—

- कुल सृजित मानव दिवस— 4257 मानव दिवस।
- कुल व्यय धनराशि श्रमांश— 8,68,500
- कुल जल संचय क्षमता— 1.31
- कुल आच्छादित ग्राम पंचायतें — 10 ग्राम पंचायतें।

कीवी के उत्पादन से आय में हुई दोगुनी वृद्धि कीवी उत्पादन कलस्टर ग्राम पंचायत बजीरा

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
पिथौरागढ़ के सौजन्य से प्राप्त

विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बजीरा पालाकुराली के अन्तर्गत प्रगतिशील कास्तकारों द्वारा बड़े पैमाने पर कीवी उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बजीरा के 40 कास्तकारों द्वारा कीवी का उत्पादन किया गया है, तथा कीवी इस वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत पालाकुराली कपणियां एवं अन्य ग्राम पंचायतों के कास्तकारों द्वारा कीवी उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 40 कास्तकारों एवं 2021-22 में 100 कास्तकारों का चयन कीवी कलस्टर हेतु ग्राम पंचायत बजीरा में किया गया था। इसमें कास्तकारों द्वारा उद्यान विभाग के सहयोग से कीवी प्लान्टेशन का कार्य किया गया है। कुल अभी तक तीनों वित्तीय वर्षों में 180 कास्तकारों को एवं एस0ई0सी0सी0 के लाभार्थियों को वरीयता दी गई है।



महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत घेरवाड स्ट्रक्चर एवं टैंक निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में घेरवाड एवं 2021-22 में एंगल स्ट्रक्चर के साथ टैंक निर्माण किया जा रहा है।

योजना से जुड़े कास्तकारों द्वारा अभी तक 30 कुन्तल कीवी से 4.5 लाख से अधिक आय अर्जित की जा चुकी है एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 10 लाख तक कास्तकारों की आय कीवी के उत्पादन से करने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कीवी कलस्टर के रूप में ग्राम पंचायत बजीरा के साथ-साथ पालाकुराली का चयन भी किया गया है जिसमें 40 कृषकों को उद्यान विभाग के सहयोग से कीवी की पौध एवं मनरेगा योजना के तहत एंगल एवं स्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जायेगा। विकासखण्ड द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक कास्तकार को कीवी कास्तकार के रूप में विकसित किया जाये।

कीवी कलस्टर द्वारा निर्मित सम्पतियों का विवरण-

- मनरेगा योजना से – टैंक घेरवाड एवं कीवी एंगल स्ट्रक्चर | उद्यान विभाग – कीवी पौध एवं तकनीकी सहायता।
- योजना की लागत- 16 लाख रु0
- सृजित मानव दिवस- 2596 मानव दिवस। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कुल चयनित कास्तकार-40

जल संरक्षण जीवन संरक्षण नैना झील पुनरुद्धार

मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग
के सौजन्य से प्राप्त

नैना झील ग्राम पंचायत डुंगरा विकास खण्ड अगस्त्यमुनी जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित एक प्राकृतिक जल निकाय है। यह ग्राम पंचायत डुंगरा से लगभग 03 किमी० बन पंचायत डुंगरा में स्थित है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डुंगरा में ग्राम पंचायत से लगभग 3 किमी० की दूरी पर यह झील स्थित है। इस स्थान पर पूर्व में वर्षाजल संवर्धित होता था। किन्तु भूमि संरक्षित न होने के कारण यह जल निकाय नष्ट होने के कगार पर था। जिस हेतु ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अवगत कराया गया, तत्पश्चात् नैना झील के पुनरुद्धार हेतु मनरेगा योजना के अन्तर्गत चयन किया गया। पूर्व में भूमि कटाव के कारण नैना झील का अस्तित्व खतरे में था। मनरेगा योजना से भूमि संरक्षण का कार्य किया गया। योजना में लगभग 400 मी० की सुरक्षा दीवार का निर्माण एवं झील के चारों तरफ बन-प्रजाति (बॉज, हरीज आदि) के पौधों का रोपण किया गया। इसकी लागत 2.00 लाख रुपये रखी गई थी। जिसका पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

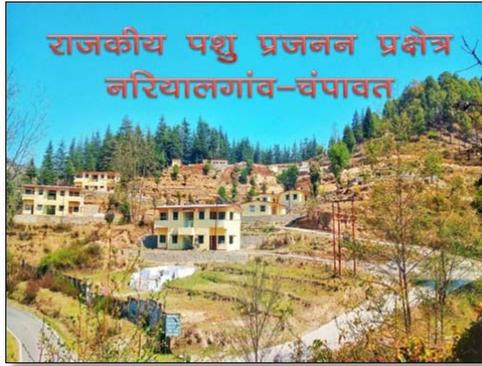


इस अभिनव प्रयास के फलस्वरूप नैना झील के जल विभाजन में आने वाले 06 ग्रामों (आरसों, डुंगरा, बनतौली, बाढ़ा, वैरागना तथा कठैत) के प्राकृतिक जल स्रोतों के स्तर में वृद्धि हुई है तथा इस झील से नीचे पड़ने वाले स्थान में घास एवं चारा प्रजाति के पौधों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

पशु प्रजनन फार्म नरियालगांव चम्पावत में हाइड्रोपोनिक्स चारा मशीन

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी चम्पावत के सौजन्य से प्राप्त

- **परिचय**— समय के साथ वनों के आच्छादन में कमी के साथ-साथ भूमि जोत में कमी के कारण किसानों की पशु धारण क्षमता में कमी आती है जिसके कारण पशु मालिक अपनी दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण विदेशी जानवरों को पसंद करते हैं। इसलिए राज्य के लिए प्रजनन नीति तैयार की गई थी जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जर्सी के क्रॉसब्रीड की सिफारिश की गई थी। कृत्रिम गर्भाधान में वृद्धि के कारण

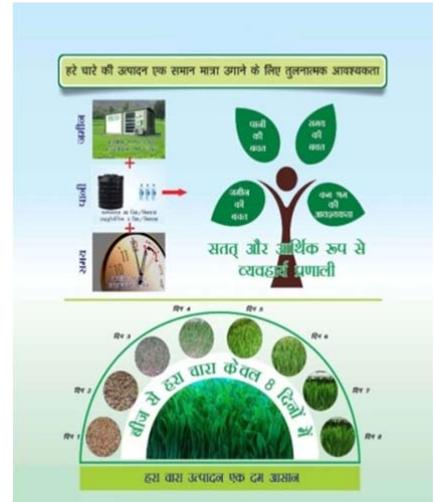


उत्तराखण्ड के स्थानीय पहाड़ी मवेशी जो पहले से गैर-मान्यता प्राप्त थे, अधिक असुरक्षित हो गए। गहन और उच्च उपज देने वाले पशुपालन के साथ समस्या यह है कि इसके लिए बहुत अधिक परिष्कृत आवास संसाधनों और सावधानीपूर्वक भोजन और अधिशेष चारे की आवश्यकता होती है, जिसकी हमारे पहाड़ी किसानों के पास कमी है। इसलिए भूमिहीन किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विकल्प होना चाहिए। इसलिए जनपद चम्पावत के नरियालगांव में

पशु प्रजनन फार्म की स्थापना 2012 में उत्तराखण्ड के स्थानीय पहाड़ी मवेशियों के संरक्षण और प्रचार के लिए की गई थी। 50 गायों से शुरू हुए इस फार्म में वर्तमान में 400 से अधिक पशुधन है।

इस फार्म में इस नस्ल की वैज्ञानिक मान्यता के लिए अपने एकजुट प्रयासों को जारी रखा और 2016 में सफल हुआ जब उत्तराखण्ड के इन मवेशियों ने उत्तराखण्ड की पहली प्रमाणित पशु नस्ल होने का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया। जब राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने इसे बद्री नस्ल (परिग्रहण संख्या INDIA_CATTLE_2400_BADRI_03040) के रूप में शामिल किया।

इन जानवरों के लिए हरे चारे की आवश्यकता की व्यवस्था करना ही एक अड़चन है क्योंकि खेत में केवल 4 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है जो साल में केवल 3 महीने ही चारा देती है। इस समस्या के समाधान के लिए बीएडीपी योजना के तहत पशु प्रजनन फार्म में 60 किलोग्राम प्रतिदिन की क्षमता वाली हाइड्रोपोनिक्स चारा मशीन स्थापित की गई हैं।



- **हाइड्रोपोनिक्स चारा मशीन**— पशुपालन में हरे चारे की आवश्यकता अनिवार्य है और सर्दियों के दौरान जमीन की कमी और हरे चारे की अनुपलब्धता के कारण जानवरों के लिए इसकी व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है। इस समस्या को जिला फोरम में रखा गया और सीमा क्षेत्र विकास योजना (बीएडीपी) के तहत 05 लाख रुपये मंजूर किए गए। चूंकि यह तकनीक पर्वतीय क्षेत्रों के लिए नई थी और बद्री मवेशियों के लिए हाइड्रोपोनिकली उगाए गए चारे के स्वाद के बारे में अनिश्चितता थी। इसलिए प्रायोगिक उद्देश्य के

लिए 60 किलोग्राम हरे चारे की क्षमता वाली मशीन क्षेत्र में स्थापित की गई थी। वैकल्पिक हरित ऊर्जा समाधान लिमिटेड द्वारा हाइड्रोपोनिक्स मशीन स्थापित की गई है। जैसा कि हमें उम्मीद थी कि हाइड्रोपोनिकली उगाया गया चारा अत्यधिक स्वादिष्ट होता है और बंदी गायें इस चारे को आसानी से खा रही थी। इस मशीन का रूपान्तरण अनुपात 1:6 है यानि 10 किलो बीज 60 किलो चारे में विकसित हो रहा है। चारे को उगाने के लिए केवल नियंत्रित तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है जिसे मशीन के एक सेंसर सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जाता था।

हाइड्रोपोनिक्स मशीन पहले से भीगे हुए बीज को तापमान और आर्द्रता नियंत्रित वातावरण प्रदान करती है (बीज को 6–12 घंटे तक भिगोया जाता है)। बीज के प्रकार के आधार पर यह 24–48 घंटों में अंकुरित हो जाता है। अंकुरित बीज को फिर मशीन के रैक में ट्रे में स्थानांतरित किया जाता है। फिर अंकुर को तापमान और आर्द्रता नियंत्रित वातावरण में 8 दिनों तक बढ़ने दिया जाता है। 08 दिनों के बाद हाइड्रोपोनिकली उगाया गया चारा कटाई के लिए तैयार है। इसे सीधे गायों को दिया जाता है। स्प्रिंकलर और फॉगर्स के लिए समय को मैनुअल रूप से इस्तेमाल किए जा रहे चारे के प्रकार के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। इस मशीन में जई, बरसीम, मक्का, ज्वार और गेहूं आसानी से उगाया जा सकता है। मशीन अत्यधिक तापमान की स्थिति में काम कर सकती है और उन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां सर्दियों में हरा चारा कम होता है।

पारंपरिक रूप से उगाए गए चारे की तुलना में हाइड्रोपोनिकली उगाया गया चारा भी बहुत पौष्टिक होता है क्योंकि यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है।

- **वर्तमान परिदृश्य**— पशु प्रजनन फार्म 5 महीने से इस मशीन का उपयोग कर रहा है और पता चला है कि हाइड्रोपोनिकली उगाया गया चारा बहुत ही सुविधाजनक और न्यूनतम पूंजी के उत्पादन करने में सक्षम है। चारा उत्पादन के लिए बड़ी भूमि के मालिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस मशीन में ऊर्ध्वाधर स्थान का उपयोग किया जाता है। इस चारे को जानवर आसानी से खा रहे हैं। यह चारा बकरी, भेड़ और खरगोश पालन के लिए भी उपयुक्त है।
- हाइड्रोपोनिकली गोन मक्का (चारा) गायों को खिलाने के लिए तैयार।
- 08 दिनों के बाद 09 इंच तक लंबे चारे की कटाई की जा सकती है।



जिलाधिकारी चम्पावत श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी व मुख्य विकास अधिकारी चम्पावत श्री आर0एस0 रावत हाइड्रोपोनिक्स मशीन का निरीक्षण करते हुए।

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, चम्पावत

सहायक निदेशक डेरी विकास एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
चम्पावत के सौजन्य से प्राप्त

अभिनव प्रयास

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, चम्पावत के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, चम्पावत द्वारा अभिनव प्रयास के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं—

1. ग्रोथ सेन्टर की स्थापना:—

चम्पावत जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रोथ सेन्टर बनाकर दुग्ध विकास के माध्यम से विकसित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में रमक (विकासखण्ड—पाटी) एवं रौसाल (विकासखण्ड—लोहाघाट) में ग्रोथ सेन्टर बनाये गये हैं तथा खटौली (विकासखण्ड—चम्पावत) में ग्रोथ सेन्टर तैयार करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय को प्रेषित किया गया है।

खटौली में दुग्ध समितियां प्रारम्भ करने हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रमक एवं रौसाल में ग्रोथ सेन्टर के माध्यम से घी एवं छुरपी तैयार कर स्थानीय लोगों का आय संवर्धन किया जा रहा है।

1.बी०ए०डी०पी० के उपरान्त की स्थिति

क्र०सं०	नाम समिति	कुल सदस्य	पेरर सदस्य	कुल दुग्ध मात्रा प्रतिदिन	कुल भुगतान प्रतिमाह (रु० में)
1	रमक	38	28	42.00	35406.00
2	कोटा	32	17	38.00	32535.00
3	मंगललेख	30	11	25.00	21825.00
	कुल	100	56	105.00	89766.00

क्र०सं०	नाम समिति	कुल सदस्य	पेरर सदस्य	कुल दुग्ध मात्रा प्रतिदिन	कुल भुगतान प्रतिमाह (रु० में)
1	रौसाल	46	32	76.00	65072.00
2	डूंगराबोरा	32	08	18.00	15714.00
3	मटियानी	30	06	12.00	10584.00
4	डनगाँव	30	18	25.00	21338.00
	कुल	138	64	131.00	112708.00

2. बी0ए0डी0पी0 योजनान्तर्गत सीमान्त क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों का आय संवर्धन करना :-

स्वरोजगार/नये सदस्यों की भागीदारी-122, प्रतिमाह आय में वृद्धि-रु0 1,79,008.00

1. बी0ए0डी0पी0 से पूर्व की स्थिति

क्र0सं0	नाम समिति	कुल सदस्य	पेरर सदस्य	कुल दुग्ध मात्रा प्रतिदिन	कुल भुगतान प्रतिमाह (रु0 में)
1	श्यामलाताल	32	18	66.66	52371.00



छुरपी को बढ़ावा देना:-

सहायक निदेशक डेरी विकास एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
चम्पावत के सौजन्य से प्राप्त

दुग्ध संघ, चम्पावत प्रदेश में पहला ऐसा दुग्ध संघ है, जहां "छुरपी" तैयार किया जा रहा है। स्कीमड मिल्क से "छुरपी", जिसे "डॉग फूड" भी कहा जाता है, तैयार किया जाता है तथा इसे बिक्री किया जाता है। इससे जहां दूध का सही उपयोग हो जाता है, वहीं संघ एवं दुग्ध उत्पादकों का आय संवर्धन होता है।



अल्मोड़ा में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अभिनव प्रयास

मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा
के सौजन्य से प्राप्त

जनपद अल्मोड़ा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत वर्तमान तक 3168 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसमें 20459 ग्रामीण महिलाएँ जुड़ी हैं साथ ही 375 ग्राम संगठन एवं 20 कलस्टर स्तरीय फ़ैडरेशन का गठन किया गया है। इसके अन्तर्गत समूहों द्वारा किये जा रहे आजीविका संवर्द्धन गतिविधियों एवं अभिनव प्रयासों का विवरण निम्नानुसार है—

- वर्तमान में एनआरएलएम योजनान्तर्गत विकास खण्ड भिकियासैण में अलकनन्दा समूह, भैसियाछाना में अम्बे व वैष्णों जागृत समूह, द्वाराहाट में भौरा समूह व नारी शक्ति सीएलएफ के द्वारा राखी के पर्व को देखते हुवे राखियां बनानी शुरू कर दी गयी है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा राखी त्योहार में आय सृजन हेतु यह एक सराहनीय प्रयास है।
- सरकार के हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जनपद के समस्त विकास खण्डों की महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा 16 हजार झण्डे बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया था जिन्हें लगभग 41 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाया गया। जो इनके कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने के साथ-साथ इनकी आय वृद्धि में भी सहायक हुआ। एनआरएलएम योजना महिलाओं को राह दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- समूह की महिलाओं द्वारा कैफ़े का संचालन :- विकास खण्ड द्वाराहाट में एनआरएलएम योजनान्तर्गत महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए सरस केन्द्र के प्रथम तल पर कैफ़े का पुनः संचालन किया गया। नारी शक्ति कलस्टर स्तरीय फ़ैडरेशन की महिलाओं द्वारा इसका सफल संचालन किया जा रहा है। **22 जुलाई 2022** को माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। सरस केन्द्र के समीप विकास खण्ड कार्यालय, कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटैक्निक कॉलेज तथा सीएचसी हॉस्पिटल आदि स्थापित है। सरस केन्द्र के उद्घाटन के उपरान्त वर्तमान तक लगभग 11132.00 रु0 की आय अर्जित की जा चुकी है। इससे महिलाओं का काफी उत्साहवर्द्धन हो रहा है।
- विकास खण्ड लमगड़ा में एनआरएलएम योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बाल मिठाई बनाने का कार्य किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा दुकान तथा विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगवाकर मिठाई का विक्रय भी किया जा रहा है।
- एनआरएलएम योजनान्तर्गत विकास खण्ड-ताकुला, लमगड़ा एवं हवालबाग की महिलाओं द्वारा मशरूम का उत्पादन एवं विपणन तथा आजीविका संवर्द्धन किया जा रहा है।
- विकास खण्ड हवालबाग एवं चौखुटिया के स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऐंपण बनाकर जीविका पालन किया जा रहा है, साथ ही अन्य महिलाओं को भी उक्त कार्य को करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।
- एनआरएलएम योजनान्तर्गत समस्त विकास खण्डों में विभिन्न आजीविका संबंधित गतिविधियां की जा रही हैं जैसे- बकरीपालन, मुर्गीपालन, दुग्ध व्यवसाय एवं मधुमक्खी पालन।
- एनआरएलएम योजनान्तर्गत महिलाएं अचार एवं बुरांश जूस का उत्पादन एवं विपणन कर रही है।
- एनआरएलएम योजनान्तर्गत कतिपय समूहों द्वारा वनाग्नि के समय आग बुझाने का उत्कृष्ट कार्य किया गया, जिसके लिये जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी समूहों द्वारा किये गये जन कल्याणकारी गतिविधियों की सराहना की गई।
- साथ ही समूह की महिलाओं द्वारा हरेला पर्व के उपलक्ष्य पर बहुतायत मात्रा में पौधारोपण किया गया। संलग्न-अनीता लोहनी ताकुला समूह सदस्य एवं गीता जोशी द्वाराहाट समूह सदस्य की सफलता की कहानी

गोलज्यू स्वयं सहायता समूह बेरीनाग, पिथौरागढ़ द्वारा कृषि यंत्रीकरण की सफलता गाथा

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
पिथौरागढ़ के सौजन्य से प्राप्त

सफलता की कहानी

कृषक –गोलज्यू स्वयं सहायता समूह

ग्राम – किरौली (बेठोली)

न्याय पंचायत – काण्डे,

विकासखण्ड – बेरीनाग।

शीर्षक –कृषि कार्यों में महिलाओं का स्वालम्बन

उपशीर्षक – पावर वीडर, स्प्रेयरमशीन, वर्मीपिट।

उद्देश्य –कृषि यंत्रीकरण।



कठिनाई – समूह की महिलायें लम्बे समय से कृषि एवं सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। खेतों को तैयार करने में लगने वाले समय, लागत और निर्भरता के कारण उनको कृषि कार्यों में अत्यधिक कठिनाई आती थी। बैलों द्वारा जुताई अधिक गहराई तक ना होने से उत्पादन में भी कमी आने लगी थी। बैलों का किराया भी अत्यधिक था। अपनी समस्या उन्होंने कृषि विभाग के कर्मचारियों को बताई। जिस क्रम में उन्हें कृषि यंत्रीकरण योजना के बारे में विस्तृत जानकारी मिली।

समाधान– विभागीय कर्मचारियों की बातों का संज्ञान रखते हुए समूह की महिलाओं के द्वारा अनुदान पर पावर वीडर क्रय करने हेतु बैठक कर एवं इससे होने वाले लाभ के विषय में भी विचार विमर्श किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप समूह द्वारा अनुदान पर पावर वीडर लिया गया। जिससे उनके कृषि कार्यों की लागत एवं समय दोनों ही कम हो गये हैं एवं गुणवत्तापूर्ण सब्जी, फसल उत्पादन किया जा रहा है। महिलायें सब्जी का स्थानीय बाजार (काण्डे किरौली) में विक्रय कर रही है। परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्मीपिट का निर्माण कराया गया जिससे वर्मी कम्पोस्ट प्राप्त होती है। इस खाद से जैविक सब्जी एवं फसल उत्पादन में वृद्धि हुयी है। जो कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है।

परिणाम – महिलाओं की कृषि कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परन्तु खेतों की तैयारी करने हेतु वे सदैव ही बैलों एवं पुरुष सदस्यों पर निर्भर रही। पावर वीडर से उनके कार्य आसान हो गये हैं। वो सब्जी उत्पादन एवं फसल उत्पादन करने हेतु खेतों की जुताई स्यवं कर रही है। साथ ही साथ वे पावर वीडर को घण्टे के हिसाब से किराये पर देकर आमदनी भी कर रही है। भविष्य में भी उन्हें इसके माध्यम से अच्छा फायदा होने का पूर्ण विश्वास है।

तुलनात्मक अध्ययन

योजनाओं के क्रियावन से पूर्व						योजनाओं के क्रियावन के पश्चात्				
क्र० सं०	कार्य	माध्यम	लागत/नाली	समय / नाली	आय	माध्यम	लागत/नाली	समय / नाली	आय/नाली	लाभ
1	जुताई	बैल	रु 350	1:50 मिनट	—	पावर वीडर	रु. 40-50	30 मिनट	रु. 250	रु. 200/नाली
2	खाद	गोबर	—	—	—	वर्मीपिट (कम्पोस्ट)	विभाग द्वारा निःशुल्क निर्माण	—	—	30% उत्पादन में वृद्धि
3	फसलों में रसायन छिड़काव (जैविक खाद/रसायन)	हाथों से	150	25 मिनट	—	नैपसेक स्प्रेयर	विभाग द्वारा निःशुल्क वितरण	15 मिनट	—	उत्पादन में वृद्धि एवं बीमारी रहित उत्पादन
4	जैविक खाद का रसायनों में प्रयोग	कृषि निवेश केन्द्रों से क्रय	150-120	25 मिनट	—	ट्राईकोर्डमा, नीम ऑयल, कन्सोटिया, नीम खली	विभाग द्वारा निःशुल्क वितरण	15 मिनट	—	जैविक सब्जी एवं फसल गुणवत्ता बढ़ी

- ❖ समूह द्वारा पावर वीडर को किराये पर देकर खरीफ 2020 में रु० 50,000 की आमदनी की गई।
- ❖ फल सब्जी उत्पादन में लगभग रु० 30,000 का मुनाफा कमाया है।